

हरियाणा विधानसभा

की

कार्यवाही

30 मार्च, 1979

खंड 1, अंक 20

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्तवार, 30 मार्च, 1979

पृष्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(20)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(20)5
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(20)18
व्यवस्था का प्र न— गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, कुरुक्षेत्र को िाफ्ट करने संबंधी	(20)19
ध्यानाकर्षण सूचना— हरियाणा राज्य से दुधारु प ़ुओं के निर्यात संबंधी	(20)22
वक्तव्य— (ए) मुख्य मंत्री द्वारा— (i) हरियाणा राज्य से दुधारु प ़ुओं के निर्यात	

संबंधी	(20)22
(ii) गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, कुरुक्षेत्र को रिफाईट करने संबंधी	(20)24
वाक आउट	(20)24
सदस्य को निकालना	(20)25
वक्तव्य (पुनराम्भ)	
(बी) सिंचाई मंत्री द्वारा लघु सिंचाई नलकूप निगम से लाभ प्राप्त करने वालों के लिए राहत उपायों की घोशणा संबंधी	(20)26
(सी) कृषि मंत्री द्वारा गवर्नमेंट मैडिकल कालेज, रोहतक में अभिकथित इररैगुलैरिटीज संबंधी	
(डी) वित्त मंत्री द्वारा हरियाणा से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर की चोरी रोकन संबंधी विधेयक को वर्तमान सेशन में पेश करने संबंधी	(20)27

	(20)30
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(20)31
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(20)33
रिपोर्टस पे ा करना—	
(i) सुबार्डिनेट लैजिस्ले ान कमेटी की दसवीं रिपोर्ट	(20)34
(ii) एस्टीमेट्स कमेटी की ग्याहरवीं रिपोर्ट	(20)34
दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 1979	(20)34
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 1979	(20)34
दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) बिल, 1979	(20)57
वाक आउट	(20)76
दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) बिल, 1979 (पुनराम्भ)	(20)

हरियाणा विधान सभा

भाकवार, 30 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

भाक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब एक मंत्री जी भाक प्रस्ताव करेंगे।

उद्योग मंत्री(डा० मंगल सैन): स्पीकर साहब, मैं बड़े कष्ट के साथ सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। 28 मार्च को, अर्थात् आज से दो दिन पहले भारत की संसद के सांसद श्री हीरा लाल पटवारी का अक्समात देहावसान हो गया। वे बड़े योग्य पार्लियामैंटेरियन थे। उनका जन्म डाबरा, जिला नागौर, राजस्थान में 16 नवम्बर, 1914 को हुआ था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा जमालपुर जिला मैमनसिंह, बंगलादे में हुई। वे 1957 से लेकर 1968 तक आसाम प्राईमरी टीचर्ज एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। जब अखिल भारतीय शिक्षकों की एक समिति बनी तो 1961 से लेकर 1972 तक अर्थात् लगातार 11 साल तक वे उसके प्रधान रहे। इनका संबंध कई सामाजिक और भौक्षणिक

संस्थाओं के साथ रहा। स्पीकर साहब, वे यूनिवर्सिटी कोर्ट के मैम्बर भी थे। वे मंगलदोई, जो आसाम में एक जिला है, उसकी जिला परिशद के अध्यक्ष भी रहे। स्पीकर साहब, इन्होंने न गाबंदी के लिए बहुत बड़े काम किए। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारी धरोहर है उनके विकास में, खेलों में और आदिवासियों के फोक म्यूजिक वगैरह में भी इनकी रुचि रही। स्पीकर साहब, आसाम के राजनैतिक जीवन में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1957 से लेकर 1962 तक और फिर 1967 से लेकर 1972 तक आसाम विधान सभा के सदस्य चुने जाते रहे। 1977 में जब लोक सभा का चुनाव हुआ उसमें भी वे चुनकर आए। स्पीकर साहब, वे गरीब के लिए, डाउनट्रोडन के विकास के लिए सदा प्रयत्न करते रहे। उनके निधन से इस सदन को बड़ा गहरा कष्ट हुआ है।

इसी प्रकार, स्पीकर साहब, हमारे एक साथी का देहावसान हुआ है जो पंजाब विधान सभा में हमारे साथ थे। उनका नाम है भगत गुरां दास हंस। उनका जन्म 12 जनवरी, 1920 को हो गियारपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा भी हो गियारपुर में पाई। स्पीकर साहब, पसमांदा जाति से संबंधित होने के कारण, बाल्मीकि परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने इस वर्ग के उत्थान के लिए बहुत काम किया। उन्हें मालूम था कि बाल्मिकि जाति के बच्चे कुछेक मजबूरियों कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। उन्होंने भागीरथ प्रयास करके हो गियारपुर क्षेत्र

में कई प्राईमरी स्कूल खुलवाएं। यही नहीं, जागीरदारों के पास जो मजारे हुआ करते थे उनको उनका हम दिलवाने के लिए और सरकार की तरफ से उनको कर्जे दिलवाने के लिए तथा अन्य सुविधाएं दिलवाने के लिए बड़े भारी प्रयास किए। वे 1952 से लेकर 1977 तक लगातार पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। वे हमारे साथी थे। स्पीकर साहब, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता का राजनीतिक नेता का, इस संसार से उठ जाना इस सदन के लिए बड़े दुःख की बात है। तो मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन को उनके निधन से गहरा कष्ट है। हम सब उनके परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं।

श्री भाम ोर सिंह(नरवाना): अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने जो भाोक प्रस्ताव पे ा किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। असम से पार्लियामेंट के मैम्बर श्री हीरा लाल पटवारी का अभी दो रोज पहले दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। इसी प्रकार पंजाब के भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 भगत गुरां दास हंस, जो सारे पंजाब के पिछड़ी हुई श्रेणी के लोगों के बहुत बड़े लीडर थे, उनका भी तीन चार रोज पहले देहान्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों विभूतियों का हमारे राजनैतिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इनके दुनिया से चले जाने से बड़ा भारी खला पैदा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, जहां मैं इनके परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं वहां मैं सदन के नोटिस में एक और महान व्यक्ति के निधन की

सूचना भी लाना चाहता हूँ। हरियाणा के सांस्कृतिक जगत के एक बहुत बड़े कलाकार, एक बड़ी महान विभूति श्री नरसिंह जी थे। वे भापड़ौदा गांव, जिला रोहतक के रहने वाले थे। उनका पिछले महीने 78 साल की उमर में निधन हुआ। उसके पांच छः रोज पहले वे मुझे मिले थे। नरसिंह जी हरियाणा के सांस्कृतिक जगत के बीरबल के नाम से जाने जाते थे। अध्यक्ष महोदय, वे आर्य समाज के भी बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। वे चौधरी छोटूराम जी के भी सहयोगी थे। अध्यक्ष महोदय, उनका ऐसे वक्त निधन हुआ, जब हरियाणा का सांस्कृतिक जगत पहले से ही बहुत पुअर है। श्री नरसिंह जी के यहां से चले जाने से उस जगत को बड़ी भारी क्षति पहुंची है। मैं आपके माध्यम से डाक्टर साहब से भी और मुख्य मंत्री जी से भी दरख्वास्त करूंगा कि उनका नाम भी इस प्रस्ताव में शामिल किया जाए। इन भाबदों के साथ मैं अपनी तरफ से इन सब महान विभूतियों को श्रद्धांजलि पे ा करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, उनका नाम इस प्रस्ताव के साथ जोड़ने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह भूल से रह गया है। मैं स्वयं उनका बड़ा ऐडमायरर रहा हूँ। निधन से कुछ दिन पहले वे मेरे पास किसी काम के लिए पधारे थे। हरियाणा मैं सांस्कृतिक चेतना लाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। इस क्षेत्र में उन्होंने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। उनके देहावसान का भी हमें बड़ा दुःख है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा(मेहम): स्पीकर साहब, डाक्टर मंगल सैन जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उसके साथ मैं भी अपने आप को भामिल करते हुए दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो भाब्द कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, श्री हीरालाल पटवारी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक दफा करनाल के अन्दर प्राईमरी स्कूलज के लिए अलग डायरेक्टोरेट बनाने के संबंध में टीचर्ज की कांफेस हुई थी और उसमें उनको आमंत्रित किया गया था। उस वक्त अध्यापकों में यह चर्चा थी एक पटवारी स्कूल के टीचर्ज के फंक्शन को क्या प्रिजाइड ओवर करेगा लेकिन आज जब डा० मंगल सैन जी ने भाोक प्रस्ताव पे आ करते हुए कहा कि उन्होंने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में, तो मुझे यह महसूस हुआ कि ऐसी महान विभूति का हमारे देश से चले जाना बहुत ही दुःख की बात है। यह क्षति पूरी नहीं की जा सकसती। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इन महान विभूतियों ने अपने जीवन में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए, जो रास्ते हमें दिखाए उन पर हमें चलना चाहिए और जो कार्य दपसे पूरे नहीं हो सके उनको उन द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चल कर हम पूरा करने का प्रयास करें। चौधरी भामदेर सिंह जी ने हमारे मरहूम बुजुर्ग श्री नर सिंह जी का जिक्र किया है। डाक्टर साहब ने बड़ी कृपा की है कि उनका नाम भी इस लिस्ट में भामिल कर दिया है। जैसा कि चौधरी भामदेर सिंह जी ने भी कहा उन्हें बीरबल के नाम से जाना जाता

था। उनके नाम के साथ एक नाम और भी जुड़ा हुआ था। उनको तारु नरसिंह जी के नाम से सभी लोग जानते हैं। जिस तरह से रेडियो पर तारु झगडू का नाम अक्सर आता था उसी तरह से तारु नरसिंह को भी लोग जानते थे। वे बहुत ही खुशामदिल थे। ऐजुकेशन पर वे बहुत ही अच्छा प्रचार करते थे। उनका प्रचार बहुत ही एजुकेटिव हुआ करता था। वे चौधरी छोट राम के कितने सहयोगी थे, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। उन्होंने जो हरियाणा के लोगों को शिक्षा दी उसे हम भूला नहीं सकते। हमारे पास दो भावदुःख में कहने के सिवाए कुछ नहीं है। भगवान उनके परिवार को यह दुःख सहने की भाक्ति प्रदान करें और उनकी आत्मा को भांति प्रदान करें।

चौधरी संत कंवर(हसनगढ़): स्पीकर साहब, माननीय डाक्टर साहब ने जो भावक प्रस्ताव सदन में पेश किया है, मैं अपने आपको उसमें शामिल करता हूँ। संसद सदस्य श्री हीरा नंद पटवारी और भगत गुरां दास हंस, पंजाब के भूतपूर्व विधायक, हमारे बीच से चले गये हैं। श्री पटवारी ने अपने राजनीतिक जीवन में जो भी सराहनीय कार्य किये उन कार्यों की वजह से वे आम छोटे कर्मचारियों में बड़े प्रिय हुए हैं। अगर कोई छोटा कर्मचारी देश की ईमानदारी से सेवा करे तो वह अपनी मेहनत के सहारे ऊंचे पद पर पहुँच सकता है। इन दो महान विभूतियों के साथ ही हरियाणा की महान विभूति चौधरी नर सिंह जी भी हमारे बीच से चले गये हैं। जिस दिन हमें यह पता चला कि चौधरी नर

सिंह जी हमारे बीच से चले गये है तो बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने तमाम जिन्दगी चौधरी छोटू राम जी के साथ बितायी। उन्होंने चौधरी देवी लाल जी के साथ भी काफी साल बिताये। वे माननीय मुख्य मंत्री के खास नजदीकी दोस्तों में से थे। अभी दो महीने पहले मेरी कांस्टीच्युएंसि में एक मीटिंग हुई थी, उसमें चौधरी नर सिंह जी भी आये हुए थे। उस मीटिंग में चौधरी बीरेंद्र सिंह और दूसरे मंत्री लोग भी आए हुए थे। वे हमे 11 जनता पार्टी के साथ रहे। वे बड़ी हिम्मतवाले थे। कांग्रेस भासनकाल में कोई गलत बात होती थी तो वे उसी वक्त उसका खंडन किया करते थे। उनमें बड़ी हिम्मत थी। अगर जनता पार्टी में कोई गलत बात होती थी या कोई गलत काम होता था तो भी वे खंडन करते थे। मैं अपने को इस भाोक प्रस्ताव में भाामिल करते हुए और उनके परिवार को सांत्वना देते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ।

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव आत हमारे सामने है उसमें हम अपने आपको भाामिल करते है। श्री हीरा नंद पटवारी जी ने जो भी काम किये है वे मेरे से पहले बोलने वाले भाईयों ने अर्ज किये है। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किये है। जहां तक भगत गुरां दास हंस का ताल्लुक है, वे हमारे साथ ज्वायंट पंजाब में मैम्बर रहे। उनके निधन पर मुझे खासतौर पर दुःख है। वे पंजाब में मेरे साथ बैठा करते थे और हम उनसे सबक लिया करते थे, उनसे म्ि वरा

किया करते थे। जो भी वे राय दिया करते थे वह बड़ी कामयाब राय समझी जाया करती थी। उनकी जुदाई से हमें बहुत दुःख है।

जहां तक श्री नर सिंह जी का संबंध है वे हरियाणा के माने हुए कवि थे। जिस तरह से पहले वक्तों में पंडित लखमी चंद और प्यारा का नाम चला करता था उसी तरह से इनका नाम भी चला आ रहा था। कोई साठ साल से हम उनका नाम सुनते आ रहे हैं। भजनों में भी श्री नर सिंह जी का नाम बड़ा मशहूर था। उन्होंने अपने टाइम में लोगों में बड़ी जागृति पैदा की। उनसे लोगों को बड़ी अच्छी शिक्षा और राय मिलती थी। इन सब की जुदाई के बाद सिवाए इसके हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को भांति पहुंचे। हम सब अपने आपको इस अफसोस में शामिल करते हैं। हमारी हमदर्दी और हमारा अफसोस उनके परिवारों तक पहुंचाया जाये।

श्री अध्यक्ष: स्वर्गीय नेताओं के बारे में जो विचार और भावनायें सदन में प्रकट की गई हैं, मैं भी अपने आपको उनमें शामिल करता हूँ। इनमें श्री हीरा नंद पटवारी ने और श्री गुरांदास हंस ने लेजिसलेटर के तौर पर देना की बड़ी सेवायें की हैं। इसी तरह से नर सिंह जी भी बहुत बहादुर और दिलेर थे। उनके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। जाति तौर पर तो उनकी ही कम है। मैं इस सदन की भावनाओं और हमदर्दी को

भाोकजदा परिवारों तक पहुंचाऊंगा। अब मैं आप से निवेदन करता हूँ कि उनकी याद में दो मिनट के लिए मौन धारण करूँ।

(इस समय दिवंगत नेताओं की याद में सदन ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान अब सवाल होंगे।

Parity amongst the M.B.B.S. Doctors and Ayurvedacharya Vaid

***925. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give equal emoluments and facilities to M.B.B.S. Doctors and Ayurvedacharya Vaid; and

(b) if so, the time by which it is likely to be implemented by Government?

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती डा० कमला वर्मा):

(क) नहीं।

(ख) भून्य।

स्वामी आदित्यवे 1: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जब वैद्य और एलोपैथिक डाक्टर समान सेवा करते हैं तो उनके वेतन में अन्तर क्यों रखा जा रहा है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस समय हरियाणा राज्य में यूनानी औशद्यालय के वैद्य नान-गजेटिड पोस्टस पर हैं। इसका कारण यह है कि पहले जो भी शिक्षण संस्थाएँ थीं वे अच्छी नहीं होती थीं, बच्चों की पढ़ाई का भी ठीक प्रबंध नहीं था। लेकिन अब उनका एडमिशन ठीक तरह से होने पर उनकी क्वालिफिकेशन भी दूसरे डाक्टरों के बराबर होगी। अब जो नियुक्ति होगी वह मैरिट के आधार पर होगी। अब पे-कमीशन को इस बात के लिए कह दिया गया है कि उनके वेतन इतने होने चाहिए।

डा० बृज मोहन गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां हरियाणा में हैं इनमें जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, ये कौन-कौन सी कंपनियों से खरीदी जाती हैं और क्या बनी बनाई खरीदी जाती है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, एक प्रचेज कमेटी बनाई हुई है। हम स्टैंडर्ड की फर्मों से टेंडर इन्वाइट करते हैं। उसके बाद जिसके रेट कम होते हैं उसको आर्डर दिये जाते हैं।

चौधरी शिव राम वर्मा: मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि आजकल देश में दस प्रकार का वातावरण बन रहा है कि आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ ज्यादा रुझान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बी०ए०एम०एस० की डिग्री एम०बी०बी०एस० के बराबर है और इनकी एम० डी० भी एक दूसरे के बराबर है तो फिर इनको बराबर वेतन देने के लिये क्यों नहीं विचार किया जाता? इनको भी उन जितनी सुविधायें देने में कितना समय लग जायेगा?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: इसका जवाब तो मैं पहले दे चुकी हूँ कि यहां पर आयुर्वेद के नाम पर दुकानें खोली हुई थी। आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थानों के नाम पर चर्चा पर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता था। अब तक जो अलग-अलग नाम से जैसे बुटाना तथा गौड़ ब्रह्मण आयुर्वेदिक कालेज खोले हुए थे, इन सब को बंद करके सिर्फ दो कालेज हरियाणा में चलाये जायेंगे। एक तो खानपुर में लड़कियों के लिये और दूसर अस्थलबोहर में लड़कों के लिये। हमने उन्हें कह दिया है कि यहां पर मैरिट पर एडमिशन होनी चाहिए। बच्चों को ऐजुकेशन देने के लिए क्वालीफाईड टीचर्स होने चाहिए। 1963 में एक वैद्य को 80 रूपये मिलते थे यानी वह नौकरी 80 रूपये में भुरु करता था। 1.2.1969 को 150 रूपये हुए और 1.5.1975 से 200 रूपये हो गये। उसके बाद 14.2.1978 में उनका वेतन 350 रूपये किया है।

चौधरी शिव राम वर्मा: यह तो महंगाई के कारण बढ़ा है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: नहीं जी, महंगाई के कारण नहीं बढ़ा। अब हमने पे—कमी इन को उनका केस भेज कर यह कह दिया है कि क्योंकि अब क्वालीफाईड डाक्टरज निकलेंगे, इसलिये उन्हें एम०बी०बी०एस० डाक्टरज के बराबर रखा जाये।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि हमारी जनता सरकार आयुर्वेदिक सिस्टम को बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा बात करते रहे है? (व्यवधान व भाोर)

उद्योग मंत्री(डा० मंगल सैन): स्पीकर साहब, यह तो इररैलेवैंट सी बात है।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, अजीब बात है कि डाक्टर साहब बीच में वैसे ही बोल पड़ते है।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछिए।

श्री देवेन्द्र भार्मा: आप मेहरबानी करके इन्हें हिदायत दें कि ये बीच में इन्टरफीयर न किया करें। ये बड़े बुजुर्ग आदमी हैं। यदि हम कुछ कहेंगे तो ये बुरा मनायेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप अपना सवाल पूछिए।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, मेरा बड़ा रैलेवेंट सवाल है कि हमारी सरकार आयुर्वेदिक सिस्टम की बढ़ौतरी के लिये क्या कर रही है? दूसरा सवाल मेरा यह है कि अभी मंत्री महोदया ने यह कह दिया कि सारे हरियाणा में सिर्फ दो आयुर्वेदिक कालेज ही रहेंगे। हमारे यहां कुरुक्षेत्र में पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी यह कह कर आये थे कि यहां का कालेज यहीं पर रहेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के आ वासन को ध्यान में रखते हुए वहां का कालेज वहीं पर रहने दिया जायेगा या उसे उठाकर कहीं और ले जायेंगे?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अगर किसी कालेज में इक्विपमेंट अच्छे नहीं होंगे, अच्छी फ़ैसिलिटीज नहीं होगी तो बच्चों को वे ट्रेनिंग नहीं दे सकेंगे। बच्चों को ट्रेनिंग अगर पूरी नहीं मिलती है तो वे कालेज उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे जो हम करने देना नहीं चाहते। चाहे आयुर्वेदिक संस्थान है या मैडिकल कालेज है, हम चाहते हैं कि वहां पर क्वालीफाईड डाक्टरज हों। हमनें यह देखा है कि अस्थलबोहर के अन्दर इन सारी चीजों का पूरा इन्तजाम है। अगर कभी कुरुक्षेत्र का कालेज बंद होगा तो वहां के बच्चों को अस्थलबोहर में ही भेजा जायेगा।

कामरेड भांकर लाल: मैं हैल्थ मिनिस्टर साहिबा से यह प्र न पूछना चाहता हूं कि क्या श्री गणपति सिंह जो हरियाणा आयुर्वेदिक बोर्ड के चेयरमैन है, क्वालीफाईड भी है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: इसका इस सवाल से कोई संबंध नहीं है।

श्री फतेह चंद विज: मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो दूसरी स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, वे अगर अपना रजिस्ट्रेशन इस स्टेट में ट्रांसफर कराना चाहें तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध तो नहीं है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अगर उसकी क्वालीफिकेशन पूरी होगी और उसके पास सर्टिफिकेट होगा फिर तो हो सकता है क्योंकि आपको भायद पता होगा कि पहले बहुत से केसिज में बोगस रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इसलिये हम अब यह सारी बातें देखकर रजिस्ट्रेशन करते हैं।

श्री अध्यक्ष: इसकी क्या कोई आल इंडिया रजिस्ट्रेशन नहीं होती?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: सेंट्रल एसोसिएशन ने कुछ क्वालीफिकेशन निर्धारित की हुई है। उन्हीं के आधार पर रजिस्ट्रेशन होती है।

चौधरी गया लाल: मैं हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से यह जानना चाहता हूं कि स्टेट में आयुर्वेदिक ही नहीं, यूनानी हस्पताल भी है। मेरे हल्के में जोहड़ा में एक यूनानी हस्पताल है, वहां पर 4-5 साल से कोई हकीम नहीं है। क्या उन यूनानी हस्पताल को आयुर्वेदिक हस्पताल में बदला जायेगा क्योंकि वहां पर कोई आदमी 4-5 साल नहीं लगा है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ.....
.....

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह एक्सपंज होना चाहिए।

Mr. Speaker: This should not be recorded.

श्री मूल चंद मंगला: मंत्री महोदया को जैसे कि यह पता ही है कि स्टेट में ज्यादातर दो किस्म की डिस्पेंसरियां हैं। एक तो आयुर्वेदिक और दूसरी एलोपैथिक। जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां हैं, उनकी हालत बहुत कमजोर है। वहां पर इंतजाम भी ठीक नहीं है और दवाईयां भी पूरी नहीं मिलती। इसलिये लोगों का रुझान एलोपैथिक डिस्पेंसरियों की तरफ ज्यादा है। दूसरे मंत्री महोदया ने यह बताया है कि स्टेट में सिर्फ दो ही आयुर्वेदिक कालेज चलाये जायेंगे.....

श्री अध्यक्ष: जरा छोटा सवाल पूछने का कश्ट करें।

श्री मूल चंद मंगला: मैं छोटा सवाल ही पूछ रहा हूँ। एक तो यह सवाल है कि दो कालेज की बजाये क्या ज्यादा कालेज खोलने का कश्ट करेंगी, और दूसरे क्या वजह है कि लोग

आजकल आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों में जाने की बजाय एलोपैथिक डिस्पेंसरियों की तरफ ज्यादा जाने लगे हैं, इसलिये क्या उनका प्रबंध ठीक करने की कोशिश करेंगे?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: जहां तक लोगों का आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों में जाने का संबंध है, हम खींच कर तो उन्हें ले जा नहीं सकते। लेकिन हमारा प्रयास जरूर रहेगा कि हम आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों को ठीक रखें।

चौधरी गंगा राम: मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार गांवों में आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज को प्रोत्साहन देने के लिये डिस्पेंसरियां चलाते समय क्या-क्या फैसिलिटीज, कंसैशन और आर्थिक मदद गांव वालों को देगी?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का मेन क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने यहां पर यह बताया है कि कुरुक्षेत्र में जो आयुर्वेदिक कालेज है, उसे बंद कर दिया जायेगा और जहां पर पढ़ाई अच्छी हो सकती है, वहां पर चलाया जायेगा। स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया को यह बताना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र में जो आयुर्वेदिक कालेज है, वह काफी दिनों से चल रहा है और वहां पर

यूनिवर्सिटी भी है। क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहां पर इस कालेज को चलने देने के लिये विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ चुका है। (व्यवधान व भाोर) मंत्री महोदया ने यह जवाब दिया हुआ है कि वे दो कालेजो पर कंसेंट्रेट कर रहे हैं। एक अस्थलबोहर और दूसरा खानपुर वाला। अगर आप कुरुक्षेत्र के बारे में कोई अलग से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिये, आपको इसका जवाब मिल जायेगा। सवाल तो आयुर्वेदिक डाक्टरों को एम0बी0बी0एस0 डाक्टरों के बराबर पे—स्केल देने के बारे में है और आप यह समझते हैं कि मंत्री महोदया तो एनसाइक्लोपीडिया है आप जब चाहें तभी एकदम से वे आपके सवाल का जवाब दे दें। यह कैसे हो सकता है? (विघ्न) I would request you not to disturb the proceedings.

Chaudhri Jagjit Singh Pohloo: Sir, we full respect for you. But they should give a reply.

Mr. Speaker: Mr. Pohloo, I would request you not to disturb the proceedings of the House. Otherwise, I will be forced to names you.

(10.00 बजे)

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने बताया कि आयुर्वेदिक शिक्षा को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि

अस्थलबोहर के आयुर्वेदिक कालेज में पांच हजार रूपये से लेकर दस हजार रूपये तक एक विद्यार्थी से चंदा लेकर दाखिला किया जाता है? यह जो चंदा लिया जाता है क्या वह सरकार की इजाजत से लिया जाता है और अगर नहीं तो क्या सरकार उसको बंद करेगी?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष से कोई चंदा नहीं लिया गया। हम सरकारी ऐड दे रहे हैं इसलिए आगे आने वाले सालों में भी चंदा नहीं लिया जाएगा। पहले लिया जाता था।

श्री भले राम: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में जो दवाइयां दी जाती हैं वे देसी ही होती हैं या वहां पर अंग्रेजी दवा भी देने की इजाजत है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अंग्रेजी दवा देने की कोई इजाजत नहीं, केवल आयुर्वेदिक दवा ही दी जाती है।

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, इस सिस्टम का नाम आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम आफ मैडीसन है। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में यूनानी भी कंबाइंड है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि यूनानी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कोई इंतजाम कर रही है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, इस सवाल से इसका कोई संबंध नहीं है।

चौधरी देसराज: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हरियाणा में कितनी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां खोली है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, 42 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां खोली है।

चौधरी लाल सिंह: क्या मंत्री महोदया, बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों में जो दवाइयां दी जाती है क्या वे किसी लेबोरेटरी में टेस्ट की जाती है? स्पीकर साहब, वे निरी मिट्टी होती है।

श्री अध्यक्ष: इस सप्लीमेंटरी का मूल सवाल से कोई संबंध नहीं है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने बताया है कि हम आयुर्वेदिक सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन हरियाणा में सिर्फ दो आयुर्वेदिक कालेज है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन कालेजों में सीटें बढ़ाने के बारे में सरकार कोई विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष: इसके लिए अलग से नोटिस दें।

डा० बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, आयुर्वेदिक कालेज से जितने भी डाक्टर क्वालिफाई होकर निकलते हैं वे आयुर्वेदिक दवाइयों को छोड़कर ऐलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल

करना भुरु कर देते है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि इस चीज पर सख्ती से अमल किया जाएगा कि किसी भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल न दिया जाए?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, वैसे तो इस सप्लीमेंटरी का मूल सवाल से कोई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूं कि हमारी पूरी कोशिश है कि आयुर्वेदिक डाक्टर आयुर्वेदिक दवाई ही इस्तेमाल करें और अंग्रेजी दवाई इस्तेमाल न करें।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि हरियाणा में कोई योग्य आयुर्वेदाचार्य नहीं है.....
.....

श्रीमती डा० कमला वर्मा: यह मैंने नहीं कहा है।

स्वामी आदित्यवे I: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि क्या हरियाणा में कोई योग्य आयुर्वेदाचार्य है जिसको एम०बी०बी०एस० के बराबर सुविधाएं दी जा रही है (व्यवधान)?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: किसी विधायक ने बीच में चेयरमैन की योग्यता के विषय में कहा था। बोर्ड के चेयरमैन श्री गनपति क्वालिफाईड है, आप यह नहीं कह सकते कि वे क्वालिफाईड नहीं है।

स्पीकर साहब, अब मैं स्वामी जी के प्रश्न का जवाब देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, अब तक यह पोस्ट गजेटिड नहीं है और एम0बी0बी0एस0 डाक्टर की पोस्ट गजेटिड है इसलिए बराबर की सुविधाएं देने का सवाल ही नहीं था। अगले साल पे—कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कोई फैसला किया जाएगा कि इसको गजेटिड पोस्ट बनाया जाए या नहीं लेकिन अभी मैं भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: स्पीकर साहब कुरुक्षेत्र में एक आयुर्वेदिक कालेज कई सालों से चल रहा है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: इस सप्लीमेंटरी का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

Cost of Ordinary, Deluxe and Air Conditioned Buses

***923. Swami Adityavesh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total cost of Ordinary, Deluxe and Air Conditioned buses separately being run by the Haryana Roadways in the state;

(b) the cost of chassis and bodies of each bus, separately referred to in part (a) above?

मुख्य संसदीय सचिव(श्री सुरेंद्र सिंह ओजला): कथन
सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

कथन

	लेलैंड 210'' व्हील ब्रेस वाईकिंग चैसिस पर प्रति बस रेट	टाटा 205'' व्हील ब्रेस चेसिस	बस रेट	
एयरकंडी ड	3,40,192	—	टाटा चैसिस पर वातानुकूलित बस बाड़ी नहीं बनवाई गई।	
डीलैक्स	1,66,059	—	1,54,412	
साधारण डिस्टिक	1,55,131	—	1,44,532	
(ख)	लेलैंड 210'' व्हील ब्रेस पर बस बाड़ी के रेट तथा वोल्टास	लेलैंड 210'' व्हील ब्रेस वाईकिंग	टाटा 205'' व्हील ब्रेस चैसिस पर प्रति बस बाड़ी रेट	टाटा 205'' व्हील ब्रेस का

	एयरकंडी ान प्लांट की कीमत	ग चैसिस का रेट		रेट
एयरकंडी ां ड	2,35,501 (जिसमें एयरकंडी ान की कीमत 1,26,301 भी भामिल है)	1,04,69 1	—	—
डीलैक्स	61,380	1,04,69 1	53,560	1,00,85 2
साधारण	50,960(आलमेंट ल)	1,09,24 1	48,360(आलमेंट ल)	1,00,85 2
डिस्टिक	43,680(कम्पोजि ट)		41,080(कम्पोजि ट)	

नोट:— एयरकंडी ां ड तथा डीलैक्स बसों के रेट 31-12-78 तक के थे ।

स्वामी आदित्यवे ा: स्पीकर साहब, एयर कंडी ां ड बस की कीमत 3 लाख 40 हजार 192 रूपए बताई गई है । डिलक्स बस की कीमत 1 लाख हजार 59 रूपए बताई गई है और साधारण

बस की कीमत 1 लाख 55 हजार 131 रूपए बताई गई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब हरियाणा में साधारण बसों की कमी है तो एयर कंडी ंड और डिलक्स बसें क्यों चलाई जा रही है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि एयर कंडी ंड बसों के होने से हरियाणा रोडवेज का नाम ऊंचा होता है क्योंकि दूसरी स्टेटस के पास इतनी अच्छी बसें नहीं है।

चौधरी ई वर सिंह: क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि डिलक्स बसों की बजाए क्या यह जरूरी नहीं होगा कि साधारण बसें चलाई जाएं?

श्री सुरेद्र सिंह ओजला: मैं ई वार सिंह जी को बताना चाहता हूं कि हमारे पास बाईस सौ बसें है उनमें सिर्फ चार एयर कंडी ंड बसें है और चौदह डिलक्स बसें हैं। तो यह कोई ज्यादा नम्बर नहीं है।

श्री देवी दास: क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि डिलक्स बस और एयर कंडी ंड बस के किराए में जो फर्क को कम किया जाएगा?

श्री सुरेद्र सिंह: ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री जय नारायण: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ़ से रोहतक के लिए डिलक्स बस चलाई जाएगी?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, डिलक्स बसों की कमी है और हमारे मैम्बर साहेबान डिलक्स बसें चलाने के लिए कह रहे हैं। जैसा आप लोगों का विचारा होगा, वैसा सोच लिया जाएगा।

चौधरी पीर चंद: स्पीकर सहाब पहले हिसार से चंडीगढ़ के लिए और हमारे मैम्बर साहेबान डिलक्स बसें चलती थीं लेकिन वे बंद कर दी गई थी। क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि उनको दोबारा चलाया जाएगा?

श्री सुरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, फिलहाल चंडीगढ़ से दिल्ली और िमला से दिल्ली को डिलैक्स बसें चलाई जा रही है। पहले यमुनानगर से दिल्ली को एक डिलक्स बस चलाई जाती थी लेकिन वह बंद कर दी गई। इस समय हमारे पास कोई डिलक्स बस नहीं है। जब हमारे पास डिलक्स बस आ जाएगी तो सब से पहले यमुनानगर से दिल्ली को चलाई जाएगी उसके बाद अगर कहीं से डिमांड आएगी तो दूसरी जगह चलाने का विचार किया जाएगा।

श्री लहरी सिंह मेहरा: स्पीकर साहब, चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब ने बताया है कि यमुनानगर से दिल्ली के लिए डिलक्स बस चलाई जाएगी। क्या चीफ पार्लियामेंटरी

सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि वह बस कब तक चलाई जाएगी?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, जब बाडी बनकर हमारे पास आ जसएगी तो सब से पहले वहीं पर डिलक्स बस चलाई जाएगी।

चौधरी राम किान: स्पीकर साहब, पहले एक डिलक्स बस चंडीगढ़ से जींद होकर हांसी जाती थी लेकिन उसको बंद कर दिया गया था। क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब उसके दोबारा चलाने पर विचार करेंगे?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: मैं पूरी तरह से इस वक्त नहीं बता सकता कि वह बस क्यों बंद की गई थी क्योंकि मेरे पास पूरी सूचना नहीं है। आमतौर से बस उस वक्त बंद की जाती है जब सवारियां न मिलती हों और कम रिसीट हो। हो सकता है कि वह बा इन्हीं कारणों से बंद की गई हो।

चौधरी भाकरुल्ला: क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ़ से गुड़गांव, सोहना, फिरोजपुर झिरका और अलवर के लिए कोई डिलक्स बस चलाने का सरकार का विचार है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: अगर डिमांड होगी तो हम जरूर चलाएंगे।

श्री हरफूल सिंह: मैं मुख्य संसदीय सचिव से जानना चाहता हूँ कि डिलक्स बसों और साधारण बसों की आमदनी बराबर होती है या कोई फर्क होता है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: जो आम बसें हैं उनके ऊपर हमारा पर-किलोमीटर का खर्चा 1.84 रु० आता है और उनसे आमदनी 1.86 रु० पर-किलोमीटर होती है। जो डिलक्स बसें हैं उन पर एक किलोमीटर के पीछे हमारा खर्चा 1.80 रु० आता है और आमदनी दो रूपए होती है।

श्री सुरेंद्र सिंह: मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब से जानना चाहता हूँ कि डिलक्स बस और एयर कंडीटेड बस की एज कितनी कितनी होती है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: सभी बसों की एज आठ-आठ साल रखी हुई है।

श्री हरफूल सिंह: इन्होंने डिलक्स बस और बस का खर्चा बताया है मैंने उनकी आमदनी पूछी थी। चूंकि डिलक्स बस में कम सवारियां बैठती हैं इसलिये मैंने पूछा था कि डिलक्स बस और आम बस की आमदनी बराबर होती है या कम?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: मैंने बताया है कि डिलक्स बस से हमें ज्यादा आमदनी होती है।

डा० बृज मोहन गुप्ता: इस सवाल से ऐसा महसूस होता है कि स्वामी जी और चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बाडी बिल्डिंग की एक कम्पनी बनाने जा रहे हैं। (हंसी)

श्री गुलजार सिंह: जैसे कि मुख्य संसदीय सचिव ने बताया कि डिलक्स बसों से आम बसों के मुकाबले में ज्यादा आमदनी होती है तो क्या वे डिलक्स बसें ज्यादा चलाने का विचार रखते हैं?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: अगर डिलक्स बसें बढ़ा दी जाएं तो आम आदमी इनके किराये का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। डिलक्स बसें उन्हीं रोड्स पर चलाई जाएंगी जहां हमें ज्यादा सवारियां मिलेगी।

श्री दीप चंद भाटिया: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या फरीदाबाद टाउन से चंडीगढ़ तक कोई डिलक्स बस चलाने का विचार है? इतनी गारंटी मैं देता हूं कि वहां से खाली बस नहीं आएगी।

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भागी राम: क्या सी०पी०एस० साहब बताने का कष्ट करेंगे जैसे उन्होंने अभी कहा कि जहां से ज्यादा सवारियां मिलेंगी वहां डिलक्स बसें चलाई जाएंगी। मेरा ख्याल है कि पैसा खर्च

करने में सिरसा जिला सबसे आगे है तो क्या सिरसा से दिल्ली को कोई डिलक्स बस चलाई जाएगी?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: मैंने पहले ही कहा है कि जहां से हमें पूरी सवारियां मिलेंगी वहां जरूर चलाएंगे। अगर सिरसा से दिल्ली की आपकी डिमांड है तो वहां से हम चला कर देख लेंगे। (गोर)

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से रिकवैस्ट करूंगा कि वे सब भली-भांति जानते हैं कि आज सै 11 का लास्ट दिन है। जैसे बोर्डिंग हाउस में हाली-डे मूड होतर है आज उसी तरह से मैम्बर साहेबान का मूड है। लेकिन मैं मैम्बर साहेबान से रिकवैस्ट करूंगा कि इस मूड के साथ साथ वे थोड़ा बहुत डिसिपलन रखने का भी ख्याल करें।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, हरियाणा में बसों की हालत बहुत खराब है और बसों की कमी भी है। क्या सी0पी0एस0 साहब बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में बसों की हालत सुधारी जाएगी और बसों की कमी कब तक पूरी की जाएगी?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: इस बात का जवाब मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं। मैंने बताया था कि यह एक ऐसा साल है जिसमें 512 नई बसें आई हैं जबकि पहले एक साल में दो

अढ़ाई सौ बसें ही आया करती थी। अगले महीने 120 बसें और आ रही हैं और मेरा ख्याल है कि उससे हालत सुधर जाएगी।

चौधरी खुरीद अहमद: मैं मुख्य संसदीय सचिव से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात उनके नोटिस में है कि कई डिलक्स बसें ऐसी हैं जो आर्डिनरी बसों से भी खराब हैं, न उसमें निकलने की जगह है और न ठीक तरह से बैठने की। तो क्या ऐसी बसों को रिप्लेस करवाया जाएगा?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: जो पुरानी डिलक्स बसें हैं उनको हम थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो नई बन रही हैं उनमें हम ज्यादा से ज्यादा फ़ैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सुमेर चंद भट्ट: स्पीकर साहब, जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ भायद उसका जवाब देने में चीफ पार्लियमेंटरी सैक्रेटरी साहब को दिक्कत आये। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या चौधरी लाल सिंह की पोजिशन का ख्याल रखते हुए साधारण बसों के अलावा कोई एयर बस खरीदने का विचार है जोकि चौधरी लाल सिंह के सुपुर्द की जाए और वे अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकें? (हंसी)

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सुरेंद्र सिंह: क्या मुख्य संसदीय सचिव बताने का कष्ट करेंगे कि हरियाणा रोडवेज की बसें प्रति दिन कितने

किलोमीटर कवर करती है और इनसे पर—किलोमीटर कितनी आमदनी है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: वैसे तो यह अलग सवाल है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब के पास तीन हजार बसें हैं और हमारे पास 2200 बसें हैं फिर भी हम डेली 6 लाख किलोमीटर कवर करते हैं जबकि पंजाब के बसें तो ज्यादा हैं लेकिन कवर वे भी इतना ही करते हैं।

चौधरी लाल सिंह: मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि बरवाला से दिल्ली बस चला करती थी और अब लोग फिर मांग कर रहे हैं कि बरवालस से वाया नारायणगढ़, सढौरा दिल्ली को बस चलाई जाए। तो क्या इस रूट पर बस चलाने का विचार किया जाएगा?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: बरवाला से सीधी दिल्ली के लिये ज्यादा सवारियां नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम चला कर देख लेंगे। अगर हमारी रसीट्स हुईं तो चला देंगे।

श्री लहरी सिंह मेहरा: स्पीकर साहब, चौधरी लाल सिंह ने बरवाला का रास्ता बताया है उन्हें कालका का बताना चाहिए था। (हंसी)

श्री मूल चंद मंगला: अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं डिलक्स बसों की डिमांड हो और सवारियां भी मिलें तो वहां जरूर चलानी चाहिए। चंडीगढ़ आगरा की अगर कोई डिमांड है और आगरा तो

ऐसी जगह है जहां की सवारियां भी मिल जायेंगी इसलिए वहां डिलक्स बस चलाने की कोशिश की जाये।

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: हमारी पूरी कोशिश होती है कि दूसरी स्टेटस में हम अपनी बसें ज्यादा से ज्यादा चलायें। क्योंकि आगरा जयपुर और इस किस्म के जो भाहर है इनके लिए टूरिस्ट ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है इसलिए अगर यू0पी0 गवर्नमेंट हमें इजाजत देगी तो इस रूट पर जरूर बस चलायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, आज की कार्यवाही थोड़ी जल्दी खत्म करनी है क्योंकि आज बाबू मल चंद जैन जी लंच दे रहे हैं। (हंसी)

चौधरी खुरीद अहमद: स्पीकर साहब, जैसा कि श्री मूल चंद मंगला जी ने कहा है कि आगरा से चंडीगढ़ डिलक्स बस चलायी जाये मैं वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि आगरा से अमृतसर स्ट्रेट बस चलाने का कोई सरकार का विचार है?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

स्वामी आदित्यवेत: इन बसों पर जो हरियाणा का खर्चा होता है उसका हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को लाभ होना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन इन बसों से कुछ व्यक्तियों को ही लाभ होता है।

श्री सुरेंद्र सिंह औजला: जैसा कि स्वामी जी ने कहा है इससे तो यह लगता है कि हम अपनी डिलक्स बसें और एयर कंडी ंड बसे बंद कर दे। दूसरी स्टेटस और दूसरी दे ां से जो खास व्यक्ति आते है उनको हम इन बसों में इधर उधर ले जाते है जिससे हमारे हरियाणा का गौरव बढता है। क्या स्वामी जी चाहते है कि हमारे हरियाणा का नाम न हो? अगर वे इस प्रकार चाहते है तो हम बंद कर देंगे।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, इस प्र ान में बसों की बाडीज बनाने का भी जिक्र आया है तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो बाडीज दूसरी स्टेटस से बनायी जाती है इनके बारे में पीछे चर्चा हुई थी कि इन में कमी ान खा लेते है। कभी सुरेंद्र सिंह कहते है कि जगन नाथ ने खा लिया तो कभी जगन नाथ कहते है कि सुरेंद्र सिंह ने खा लिया। पिछले साल बीस लाख रूपये की एक वर्क ाप फरीदाबाद में खोलने की स्कीम थी जहां सरकार ने बसों की बाडीज बनवानी थी अगर वह स्कीम मंजूर हो जाती है तो इससे कमी ान का झगड़ा ही खत्म हो जायेगा तो क्या फरीदाबाद में लार्ज स्केल पर ऐसी वर्क ाप चलाने की कोई योजना है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: पहले भी हाउस में इसके बारे में बताया जा चुका कि हम सब यही चाहते है कि हरियाणा में ही बसों की बाडिज बनायी जायें। इसके अतिरिक्त उस वर्क ाप के भुरू होने के अलावा हमारे पास जो थोड़ी बहुत एग्जिस्टिंग फ़ैसिलिटीज है उनसे गुड़गांव में हमने दिसम्बर में 8, जनवरी में

10, फरवरी में 12 बाडीज बनाई है और अब मार्च में 17 बाडीज बनाने जा रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हम इसी साल वर्क अप भुरू कर देंगे। जहां तक पैसे खाने का सवाल है वह मैं बताना चाहूंगा कि उसके अन्दर किसी भी सी०पी०एस० या मंत्री का ताल्लुक नहीं होता और ये जो बाडीज अलाट की जाती है उसके लिए कमी नर फाइनेंस और दूसरे अफसरान होते हैं जैसे सैक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, एस०टी०सी०, डी०टी०सी० ज्वायंट एस०टी०सी०।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, हरियाणा के एक अम्बाला जिला को छोड़कर बाकी दस जिलों से चंडीगढ़ आने के लिए आमतौर पर दो ही रास्ते हैं। एक तो जी०टी० रोड से अम्बाला कैंट होकर आते हैं दूसरा रास्ता अम्बाला भाहर से पेहवा-कैथल होकर है जो हिसार की तरफ भी चला जाता है। तो यह जो सी०पी०एस० साहब ने बताया कि चार एयर कंडी ंड और 14 डिलक्स बसें जो हैं वे सारी की सारी जी०टी० रोड से निकलती हैं जबकि दूसरा रास्ता भी उतना ही लम्बा है लेकिन उधर से एक भी एयर कंडी ंड या डिलक्स बस नहीं निकलती इसका क्या कारण है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: अध्यक्ष महोदय, डिलक्स बसिज के बारे में कई मैम्बर साहेबान ने डिमांड की है। इसको जरूर कंसिडर किया जायेगा। हमारी कोर्िा होगी कि ज्यादा से ज्यादा डिलक्स बसें आगे बढ़ाए और जो इस किस्म के रूट्स हैं

जैसे चंडीगढ़-हिसार, चंडीगढ़-आगरा और दिल्ली से जयपुर इन रूट्स पर हम डिलक्स बसें चलाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब सवालों का समय समाप्त होता है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Enquiry against the Member of Yamuna Nagar Sugar Cane Cooperative Society

280. Shri Kanhiya Lal Poswal: Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state-

(a) whether any enquiry was held against the member of Yamuna Nagar Sugar Cane Cooperative Society, Jagadhri, on the complaint of Shri Zohra Singh, Advocate, Jagadhri;

(b) if so, the detail of finding of the said Inquiry; and

(c) the action taken thereon?

कृषि मंत्री(बिग्रेडियर रण सिंह):

(ए) इस संबंध में श्री जोरा सिंह, एडवोकेट जगाधरी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(बी) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सी) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भाम ोर सिंह: स्पीकर साहब, मैं एक महत्वपूर्ण घटना जो लाबी में घटी है बताना चाहता हूँ।.....

.....

श्री अध्यक्ष: पोर्टफोलियों की बात यहां अलाउड नहीं है।
I think, this has no relevance.

उद्योग मंत्री(डा० मंगल सैन):.....

.....

श्री भाम ोर सिंह:

.....

डा० मंगल सैन: यह रिकार्ड नहीं होना चाहिए।

Mr. Speaker: This will not be recorded.

श्री भाम ोर सिंह:.....

Mr. Speaker: This is not the place to discuss that
now.

व्यवस्था का प्र न

गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, कुरुक्षेत्र को िफ्ट करने
संबंधी

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, क्वै चन आवर में आयुर्वेदिक वैद्यों का सवाल आया था.....

(इस समय कई मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष: आपका प्वायंट क्या है? अगर आप सब इक्ठे बोलेंगे तो सुनाइ कैसे देगा? एक मैम्बर बोले।

श्री देवेन्द्र भार्मा: हम आयुर्वेदिक सिस्टम को बढ़ाना चाहते है.....

श्री अध्यक्ष: यह तो क्वै चन आवर में सवाल आया थ, उस समय पूछना चाहिए था।

श्री देवेन्द्र भार्मा: तो आप जीरो आवर में क्या करेंगे?

Mr. Speaker: You must give me something in writing. (विघ्न एवं भाोर)

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, हम आयुर्वेदिक शिक्षा को बढ़ाना चाहते है परन्तु सरकार कुरुक्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेज को बंद करन जा रही है

श्री अध्यक्ष: आप इस संबंध में रैजोल्यू न लायें और हाउस में जब मोान मूव होगा, तब आप बात कर सकते है। I would request you now to please take your seat.

श्री देवेन्द्र भार्मा: यह एक इम्पोर्टेंट मसला है.....

Mr. Speaker: You kindly come and see me in my chamber.

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र से जो आयुर्वेदिक कालेज हटाया गया है, उसके बारे में मैं आपसे रिकवैस्ट करना चाहता हूँ.....

Mr. Speaker: There is no provision for taking up the point on Kurukshetra Ayurvedic College.

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, यह बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है, हमें कुछ कहने का मौका तो दीजिए?

Mr. Speaker: I give you two minutes to state your point.

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, सी०एम साहब थोड़े दिन पहले कुरुक्षेत्र गए थे उस वक्त उनसे रिकवैस्ट की थी कि आयुर्वेदिक कालेज को यहीं पर रखा जाए और जो-जो फ़ैसिलिटीज दूसरे मैडिकल कालेजिज को दी जाती है, वे इसको भी दी जाएं। लेकिन सरकार वे फ़ैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही। (व्यवधान) जब मिनिस्टर साहिबा सवाल का जवाब दे रही थी तो डा० मंगल सैन जी ने बीच में दखल दिया था और जवाब नहीं देने दे रहे थे। ये खामखाह बीच में दखलअंदाजी करते रहते हैं...

.....

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं इस पर आब्जैक्ट करता हूँ। He should not be given a licence to speak.

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर देवेन्द्र भार्मा, आप बैठिए। जो भी मैम्बर कोई प्वायंट रेज करना चाहता है, मैं उसको फुल अपौरचुनिटी देता हूँ लेकिन बीच में इधर उधर की बातें नहीं लानी चाहिए। आपका प्वायंट यह है कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, कुरुक्षेत्र को बंद करने के बारे में फिर विचार कर लें। There is no point involving other Ministers in it. You can make your point and we can request the Government to consider it. (Interruptions) There is no point involving other Ministers and making false allegations against them. I would request the hon. Members to be more careful in the words/language they use.

श्री देवेन्द्र भार्मा: आप मुझे दो मिनट बोलने दें।.....

.....

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। Nothing will be recorded.

आवाजें:

.....

श्री कंवल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। कल हाउस के आग्रह पर मुख्य मंत्री महोद ने अपनी कोठी में वापिस जाना स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसके बाद हमने प्रोपेगंडा सुना है कि यह सारे मिनिस्टर्ज पर भी लागू है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। अगर आपके पास कोई डैफिनिट सूचना है तो आप कहिए। प्रोपेगंडा के बेसिज पर आप जो बात कर रहे हैं, यह प्रौपर नहीं है।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, सैक्टर 7 में वजीरों की कोठियां हैं हमारे वजीर उनमें जा सकते हैं.....

.....

श्री अध्यक्ष: अगर आपके पास कोई डैफिनिट सूचना है तो बात करें। I will not accept any point of order based on propaganda. Please take your seat.

ध्यानाकर्षण सूचना—

हरियाणा राज्य के दुधारू पशुओं के निर्यात संबंधी

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, हमारे जींद एरिया में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। लोग नाजायज तरीके से गऊओं को ले जाते हैं..

Mr. Speaker: This is no point of order. Please take your seat.

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटेंशन मोशन दिया था लेकिन उसके बारे में मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली कि उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष: आप अपने काल अटैं इन मो इन की फेट जानना चाहते हैं, वह मैं आपको बता देता हूँ, कृपया आप बैठिए।

मैम्बर साहेबान, मुझे श्री मांगे राम गुप्ता का काल अटैं इन मो इन मिला था जिसका विशय था कि हरियाणा से गउओं की जो एक्सपोर्ट होती है, वह बंद की जाए। मैंने इसको डिस-अलाउ कर दिया है क्योंकि यह काल अटैं इन मो इन का विशय नहीं बनता। हरियाणा से जो गउएं एक्सपोर्ट होती है, उसकी एक्सपोर्ट कल या परसों तक भुरु नहीं हुई तकरीबन 20-25 साल से जारी है। काल अटैं इन मो इन एडमिट करने का कार्टेरिया यह है कि मैटर अर्जेट पब्लिक इम्पोर्ट्स का और रीसेंट अकरेंस का होना चाहिए। गउओं की एक्सपोर्ट का मामला रीसेंट अकरेंस नहीं है बल्कि कंटीन्युइंग नेचर का मामला है जो काल अटैं इन मो इन का विशय नहीं बनता। इसलिए मैंने इसको डिसअलाउ किया है। (व्यवधान एवं भाोर)

वक्तव्य—

(ए) मुख्य मंत्री द्वारा— (i) हरियाणा राज्य से दुधारु प गुओं के निर्या संबंधी

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, यह एक ऐसा सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया ध्यान दीजिए। मुख्य मंत्री साहब कुछ कहना चाहते हैं, इनको सुन लीजिए। (व्यवधान)

चौधरी देवी लाल: ठीक है, काल अटैं इन मो इन डिसअलाऊ किया है, लेकिन मैं आपकी इंफर्मे इन के लिए कह देता हूं कि 24-25 तारीख को मैं बम्बई गया था और सर्वोदय नेता दादा धर्माधिकारी से मैंने इस बात का जिक्र किया था। उसके बाद मैंने आफिसर्ज से सलाह की। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कांस्टीच्यु इनली हम गउओं की एक्सपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन हमने टैक्सिज बढ़ाने का फैसला किया है ताकि हरियाणा की गउएं कलकता न जा सकें।

श्रीमती सुशमा स्वराज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, यह जो अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस और कन्टीन्युइंग नेचर की बात.....

Mr. Speaker: Has it anything to do with the export of cows?

Shrimati Sushma Swaraj: Nothing.

Mr. Speaker: Then what do you want to say?

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, आपने रूलिंग दी है कि कन्टीन्युइंग नेचर का मामला रीसेंट अकरेंस का नहीं होता। इस पर मैं डिफर करती हूं और मेरा टैक्नीकल डिफ्रेंस है। काज आफ एव इन लीगल टर्म्ज में रीसेंट अकरेंस का मामला बनता है क्योंकि 'काज आफ एव इन' अब भी चल रहा है। That is more than 'recent occurrence'.

Mr. Speaker: Please sit down. I will not admit any point of order against my ruling.

श्रीमती सुशमा स्वराज: मैं आपकी रूलिंग को चैलेंज नहीं कर रही। यह मामला तो अब भी चल रहा है, डेली गउओं को बाहर भेजा जा रहा है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: Please take your seat. You can discuss it in my chamber.

चौधरी ि तव राम वर्मा:

.....

श्री अध्यक्ष: कुरुक्षेत्र कालेज का मामला क्लोज हो चुका है। श्री देवेन्द्र भार्मा ने रिक्वैस्ट की है वह गवर्नमेंट के नोटिस में आ गई है।

श्री देवेन्द्र भार्मा:

Mr. Speaker: Nothing will be recorded about Kurukshetra Ayurvedic College.

आवाजे:.....

....

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: मुख्य मंत्री तथा हैल्थ मिनिस्टर यहां बैठे हैं, वे इस संबंध में कोई कमिटी दे सकते हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker: Government is in no position to give any commitment at her moment. (Interruptions)

मैम्बर साहेबान, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आपको गवर्नमेंट की वर्किंग को समझना चाहिए। एक प्वायंट आप रोज करते हैं और उसका फैसला फौरन चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है? आपका प्वायंट आ चुका है, गवर्नमेंट इसको कंसिडर करेगी।

(ii) गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, कुरुक्षेत्र को रिफाईट करने संबंधी

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, एक ऐसा सवाल यहां उठाया गया जिसका अगर मुझे ठीक समय पर नोटिस मिलता तो मैं जवाब देता लेकिन फिर भी जितनी मुझे वाकफियत है उससे मैं यह बता दू कि इस कालेज को वहां चलाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की परन्तु जिस तरीके से वहां पैसा बरबाद किया जा रहा था उसको देखते हुए मैं उसे जारी रखने नहीं देना चाहता। यह पैसा, स्पीकर साहब, गर्लज कालेज खानपुर और अस्थलबोहर कालेज, को अच्छी तरह से चलाने के लिए खर्च किया जाएगा। हमारे पास कितने रिसोर्सिज है, किस तरीके से यह कालेज चलाया गया, यह सारी रिपोर्ट आपके सामने किसी मौके पर पेश कर दी जाएगी।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष: जब लीडर आफ दि हाउस ने स्टैटमेंट दे दिया तो इस पर कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं रहती।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी आप थोड़ी पे रिस रखना सीखिए। (गोर) आप बैठ जाइए।

स्वामी आदित्यवे I: मैं बहुत पहले से खड़ा हो रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: यह तो मैंने देखा है कि कौन कब खड़ा हो रहा है।

वाक आउट

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, हमें कोई मैडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही है। हमारे पांच जिलों में कोई कालेज नहीं है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: कुरुक्षेत्र के बारे में मैं काफी कह चुका हूँ। मुख्य मंत्री जी भी इसके बारे में काफी कह चुके हैं। इसलिए इस संबंध में ज्यादा बात करना भाभा नहीं देता।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: अगर यह बात है तो हम कुरुक्षेत्र जिले के सभी सदस्य एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं। (गोर)

(इस समय चौधरी जगजीत सिंह पोहलू, चौधरी ई वर सिंह, श्री लहरी सिंह मेहरा, श्री रघुनाथ गोयल और श्री देवेंद्र भार्मा सदन से वाक आउट कर गए)

सदस्य को निकालना

स्वामी आदित्यवे T: स्पीकर साहब, मेरी प्रिवलेज मो Tन का क्या हुआ? मैंने आपके चैम्बर में भी उसके बारे में आपसे रिक्वैस्ट की थी।

श्री अध्यक्ष: आपकी प्रिवलेज मो Tन डिसअलाउ हो गई है। उस रूलिंग के ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते।

स्वामी आदित्यवे T: किस नियम के तहत डिसअलाउ हुई है?

श्री अध्यक्ष: वह आप मेरे चैम्बर में आकर पूछ लेना।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, ये जो दो तीन एम0एल0एज0 बाहर के बन कर आ गए है ये हाउस को बहुत डिसटर्ब करते रहते है और अन्य किसी मैम्बर को बोलने नहीं देते। यही नहीं ये आपकी रूलिंग को भी नहीं मानते। इसलिए इन बाहर वाल एम0एल0एज0 को हाउस से बाहर निकाल देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए।

स्वामी आदित्यवे T: अध्यक्ष महोदय.....

.....

Mr. Speaker: Swamin ji, please take your seat. Otherwise, I will have to name you.

स्वामी आदित्यवे T: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए।

Mr. Speaker: I name Swami Adityavesh. He may please withdraw from the House.

स्वामी आदित्यवे T: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए।

Mr. Speaker: Swami ji, please withdraw from the House.

(Swami Adityavesh did not leave the House)

Mr. Speaker: Alright, remove Swamin Adityavesh from the House.

(At this stage the Sergeant-at-arms went to the seat of the hon. Member, Swami Adityavesh and requested him to leave the House as ordered by the Speaker. Swami Adityavesh then left the House)

वक्तव्य (पुनराम्भ)

(बी) सिंचाई मंत्री द्वारा लघु सिंचाई नलकूप निगम से लाभ प्राप्त करने वालों के लिए राहत उपायों घोशणा संबंधी

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): स्पीकर साहब, इसी सदन में चौधरी हरस्वरूप बूरा जी ने एम0आई0टी0सी0 के बारे में एक काल अटैंशन मूव की थी जो बाद में उन्होंने विदग्ध कर ली। स्पीकर साहब, इस वक्त सारे हरियाणा में जो एम0आई0टी0सी0 का काम चल रहा है वह खाल पक्का करने का है। स्पीकर साहब, सारे हरियाणा प्रदेश में िकायत आ रही थी कि उनसे जो खाल पक्का करने के पैसे वसूल किए जाते हैं वे बहुत ज्यादा हैं। सरकार काफी दिनों से यह विचार कर रही थी कि इस मामले को पूरे गौर से देखा जाए और यह विचार किया जाए कि क्या कोई ऐसी वजूहात हो सकती है जिनसे किसानों के ऊपर जो खर्च बढ़ रहा है उसको थोड़ा कम कर सकें। सरकार इस समय सात से नौ साल तक हर 6 महीने की किताब के हिसाब से 14 या 18 किताबों में 35 रुपये से लेकर 45 रुपये तक फी एकड़ के हिसाब से खाल पक्का करने का खर्च वसूल करती रही है। खाल पक्का करने से बीस फीसदी आबपा भी बढ़ जाती है। इससे किसानों को फायदा तो होता है लेकिन कई किसान बहुत महसूस कर रहे हैं कि खर्चा ज्यादा है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि हम कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिनसे किसानों को यह खर्च कुछ कम देना पड़े। सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:—

1. एम0 आई0 टी0 सी0 सूद की भारह उतनी चार्ज करेगी जो ए0 आर0 डी0 सी0 इनसे करेगी। इस भाहर में कमी करने का सरकार ने फैसला किया है।

2. खालों को पक्का करने से जो आबपा ि के कारण आमदनी बढ़ेगी इसकी एवज में गवर्नमेंट खालों की लागत वसूली जो किसानों से करती है इसमें कमी करेगी।

3. एम0 आई0 टी0 सी0 का ओवरहैड खर्चा जो इस वक्त साढ़े सताईस फीसदी लिया जाता है उसको कम किया जाएगा।

4. वसूली नौ साल की बजाय 12 साल में करने का फैसला किया जा रहा है यानी गवर्नमेंट कर्जा जमींदारों से बारह सालों में वसूल करेगी और ए0आर0डी0सी0 को नौ सालों में वापिस करेगी।

स्पीकर साहब, इस तरह से जो टोटल रिलीफ सरकार अनाउंस करना चाहती है वह तीस प्रति ात है। (प्र ांसा)

स्पीकर साहब, इसके अलावा इस किस्म की भी ि ाकायतें थी कि मैटीरियल ठीक नहीं लग रहा है। सीमेंट की भी कुछ ि ाकायत आयी थी। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि मैटीरियल के लिए एक टैक्निकल सैल मुकर्रर किया जाएगा जिसका काम मैटीरियल को तसल्लीबख्भा हालत में रखना होगा।

सीमेंट जो वहां इस्तेमाल किया जाएगा उस पर एक स्पै ल नि ान लगाया जाएगा ताकि इसकी चोरी बंद हो सके। (प्र ांसा)

(सी)—कृशि मंत्री द्वारा गवर्नमेंट मैडिकल कालेज, रोहतक में अभिकथित इररैगुलैरिटीज संबंधी।

कृशि मंत्री(बिग्रेडियर रण सिंह): स्पीकर साहब, मेरे साथी चौधरी कंवल सिंह जी ने परसों सदन में मैडिकल कालेज के बारे में कुछ बातें कहीं। मैं समझता हूं उससे भायद जनता में और प्रैस में कुछ गलतफहमी हो जाएगी। इसका हमारी पार्टी पर और हमारी सरकार पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए पब्लिक इंस्ट्रैस्ट में मैं कुछ बातों की सफाई इस सदन में देना चाहता हूं।

स्पीकर साहब, पहले तो उन्होंने यह बात कही कि मैडिकल कालेज में छापा मारा गया और वहां से कुछ सीरा मिला। उन्होंने यह भी कहा कि वह आउट आफ डेट था यानी उसकी प्रयोग करने डेट ऐक्सपायर हो चुकी थी। फिर उन्होंने कहा कि डी०सी० साहब चूंकि रैंड कास के चेयरमैन है इसलिए उन्होंने होम मिनिस्टर साहब से बातचीत करके उस केस को ड्रॉप कर दिया। यह बात सच नहीं है। ठीक है रेड हुआ, छापा मरा गया लेकिन वह छापा खुद डी०सी० ने लगवाया था। उसने अपने जी०ए० और डी०एस०पी० को यह कहकर भेजा था कि जाकर चैक करो कि वहां पर क्या गोलमाल है। वहां पर हमने 3300 मिलीलीटर दवाई

ली थी। उसमें से 420 मिलीलीटर दवाई ऐसी थी जो ऐक्सपायर होने वाली थी, अभी तक हुई नहीं थी। हस्पताल में जो अथौरटीज है उन्होंने इसे अपनी लैबोरेटरीज में टैस्ट कराया था कि आया यह और चल सकती है या नहीं। लैबोरेटरीज वालों ने कहा कि यह ठीक है और महीना दो महीने और चल सकती है। फिर दिल्ली से एक टीम लाई गई, उससे भी जांच पड़ताल कराई गई और उसने भी यह रिपोर्ट दी। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा अपने साथियों को यह भी बताना चाहता हूँ कि यहीं पर ही नहीं, इसी मैडिकल कालेज में ही नहीं बल्कि यह चीज हर कालेज में होती है न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि सारी दुनिया भर में होती है।

बैलेंस में दवाई का एक हिस्सा या दो हिस्सा बच भी जाता है। इसका मुझे भी तुजर्बा है कि डेट ऐक्सपायर हो चुकी हो और उसमें भाक्ति हो तो दो चार महीने ज्यादा भी चल सकती है। यह ठीक है कि पोटेंशियलिटी कम हो जाती है, उससे री-एक्शन भी हो सकता है। डाक्टर खुद लैबोरेटरी में टैस्ट करते हैं अगर वह ठीक हो तो उसको इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते हैं। यह कोई खास बात नहीं थी।

दूसरे उन्होंने एक्शन के बारे में कहा है। एक्शन हम ले चुके हैं। हमने पुलिस में रिपोर्ट भेजी है। पुलिस ने कलियर कर दिया कि इसमें कोई मामला नहीं है।

फिर उन्होंने कहा कि हस्पताल पर छापा मारा तो हजारों रूपए की कई चीजें मिली। उन्होंने कहा कि 30 बैड— गिटस मिली है। इस बारे में भी मैं क्लैरिफिके इन देना चाहता हूँ। मेरे को दिसम्बर के महीने में खबर मिली थी कि कुछ गोलमाल है। कई दफा जितना इन्डेंट होता है उससे कम भेज देते हैं और बाकी अपने पास रख लेते हैं। फिर उसको बाद में कहीं न कहीं दुकानदार को बेच देते हैं। मैंने मैनेजिंग कमेटी के सुपरिनटेंडेंट को बुलाया कि इसको बंद करने का कोई न कोई तरीका निकाला जायें ताकि नुकसान न हो। मेरी अपनी कांस्टीच्युएन्सी बेरी के डीघल गांव के प्राइमरी हैल्थ सेंटर की खबर मिली थी। हमने एक इंटेलीजेंस ब्यूरो बनाया, जिसमें 10—12 आदमी हैं। बीस रोज बाद छापा मारा। उसके अन्दर एक हजार की ही नहीं, आठ हजार की दवाई पकड़ी। दूसरे छापे में दो हजार की दवाईयां मिली तथा तीसरे छापे में गाज, काटन वगैरह का एक हजार 500 रूपये का समान मिला। इस बारे में पिछले दिनों हमारी गवर्निंग बाडी की मीटिंग हुई उसके फैसले पर वाहं के कर्मचारी नौकरी से बरखास्त हो गए थे लेकिन हमारे डायरेक्टर, प्रिंसिपल और एस0एस0पी0 साहब गौर कर रहे हैं कि आया इनको कोर्ट में ले जाये या नहीं। इस बात की तो हमें भाबा गी मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एग्रों इंडस्ट्रीज के बारे में कहा। उसके बारे में सब कुछ बताया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में कहा। उसके बारे में सब कुछ बताया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने मैडिकोज

की स्ट्राइक का भी जिक्र किया कि उनको तो सब कुछ दे दिया है जिन्होंने हड़ताल की थी लेकिन जिन्होंने इतने इम्पोर्टेंट टाइम में मदद की है और मरीजों की सेवायें की है उनके लिए कुछ नहीं किया है। हमने आज से दो महीने पहले फैसला ले लिया था कि इन इन को एवार्ड दिया जायेगा लेकिन मुक्ति कल उस समय आ गई जब एक लिस्ट तो वाइस चांसलर की आ गई और एक हैड आफ दि डिपार्टमेंट की तरफ से आ गई। आप जानते हैं कि एवार्ड तो काम के मुताबिक दिया जात है। इसलिए हमें दूसरी सब-कमेटी बनानी पड़ी और फैसला किया कि हरेक केस की मैरिट में जाए और जिसने फालतू काम किया है उसको इंक्रीमेंट दें। यह फैसला गवर्निंग बाडी में यूनानीमस हुआ है। पहले कुछ और मामला था, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता एक राय से फैसला किया है कि जिन मैडिकोज ने अच्छा काम किया है उन्हें काम के मुताबिक इनाम दिया जायेगा। आखिरी चीज जो उन्होंने मैं उन की है वह डाक्टर हजारी लाल के बारे में कही। 12 मार्च, को बैठक हुई थी, उस टाइम पर एजेंडा में 74 आईटम्ज थी। 10 बजे तक बैठक भुरु हुई थी और साढ़े छः बजे तक बैठक चलती रही। तकरीबन 60 आईटम्ज तो खत्म हो गये लेकिन 10-12 आईटम्ज बकाया रहे थे जिनमें हजारी लाल जी का भी नाम था। लेकिन समय की कमी होने के कारण से उस पर ठीक तरह से विचार नहीं किया जा सका। मेरा ख्याल है कि अगली बार इस बारे में विचार किया जा सकेगा और उनको मौका दिया जायेगा।

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उस पर मैं ब्रीफली अर्ज करना चाहता हूँ।

Mr. Speaker: There can be no discussion on a statement made by a Minister.

Shri Shamsheer Singh: I do not want to discuss the statement. स्पीकर साहब, इन्होंने एग्री इंडस्ट्री का जिक्र किया। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताया। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: मैं आपके सामने रूल 64 पढ़ देता हूँ। ट्रांसले ान करना तो मुि कल है लेकिन फिर भी मैं ट्रांसलै ान करने की कोि ा ा करूंगा। उसमें यह लिखा है:

'64. A statement may be made by a Minister on a matter of publice importance with the permission of the Speaker but not questions shall be asked nor discussion take place thereon at the time the statement is made.'

यानी कोई मंत्री स्पीकर की इजाजत से पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामले पर स्टेटमेंट दे सकता है लेकिन स्टेटमेंट देने के बाद उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जायेगा और न ही उस पर बहस की जायेगी।

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने जो दवाइयों के बारे में स्टेटमेंट दी है, (व्यवधान एवं भाोर)

Mr. Speaker: I will not allow any discussion. Please take your seat.

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों को रिलीफ देने के बारे में अनाउन्समेंट की है लेकिन यह रिलीफ कब से लागू होगी, यह उन्होंने नहीं बताया है। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: अब इस पर कोई डिस्कान नहीं होगी। मेहरबानी करके आप बैठ जाइए।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि यह कब से लागू होगी?

Mr. Speaker: I am sorry, I will not allow any discussion on the statement made by the Minister. Please take your seat.

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, मैंने एक प्राइवेट मैम्बर्ज रैजोल्यूशन दिया था लेकिन वह आज तक हाउस में नहीं आया है (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: वह बैलट में नहीं आया होगा। उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। जो प्राइवेट मैम्बर्ज रैजोल्यूशन बैलट में आ गये, वे एजेंडे पर आ गये हैं। चार प्रस्ताव बैलट में आये थे, जो लिस्ट आफ बिजनैस पर आ गये हैं।

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। कल हमारे साथी ने कुछ बातें कहीं। उसके जवाब में मिनिस्टर महोदय ने कहा कि मैम्बर साहब ने मिस-लीडिंग

स्टेटमेंट दी है। इस बात को कलियर किया जाये कि कौन सी बात सच है आया मिनिस्टर की बात ठीक है या मैम्बर की ठीक है।

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर के स्टेटमेंट देने के बाद कोई बात डिस्कस नहीं हो सकती अगर आप कोई प्वायंट रेज करना चाहते है तो मुझे लिखित में दें।

(डी) वित्त मंत्री द्वारा हरियाणा से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर की चोरी रोकने संबंधी विधेयक को वर्तमान सै ान में पे ा न करने संबंधी।

वित्त मंत्री(श्री मूल चंद जैन): स्पीकर साहब, इस प्रस्ताव को पे ा करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने बजट स्पीच में भी यकीन दिलाया था और उसके बाद हाउस में भी यकीन दिलाया था कि हरियाणा से बाहर जाने वाली चीजें, जैसे सोनीपत से या बहादुरगढ़ से दिल्ली को या अन्य जगह जाती है उनके टैक्स इवेजन के बारे में इसी सै ान में बिल लाया जायेगा। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि उसके बारे में हमें लीगल एडवाइस मिली है कि बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के वह बिल हाउस में नहीं आ सकता। इस कारण से हम इस बिल को इस सै ान में पे ा नहीं कर सके है। हमने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उसे भेज दिया है। आज हाउस एडजर्न होने जा रहा है लेकिन

ज्यों ही राष्ट्रपति की मंजूरी उस बिल के बारे में आ जायेगी हम आर्डिनैस के जरिए से उसको लागू कर देंगे।

श्री भाम ार सिंह: आर्डिनैस के जरिए लागू नहीं होना चाहिए। ऐसा करने तो बिल्कुल गलत बात होगी।

श्री अध्यक्ष: This is a prerogative of Government. आर्डिनैस के जरिए जारी कर सकती है। वह भी कानून के तहत लागू हो सकता है।

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने यहां पर यह वि वास दिलाया था कि इसी सै ान में वह बिल लायेंगे लेकिन अब ये मुकर्रर रहे है।

(11.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: उसी के बारे में तो इन्होंने यहां बताया कि उसमें राष्ट्रपति जी की मंजूरी लेना जरूरी है इसलिये वह नहीं हो सका।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now I will request Shri Mool Chand Jaim, Minister for Parliament affairs, to move the motion under Rule 15.

वित्त मंत्री(श्री मूल चंद जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मर्दों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकों" के उप-बंधों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मर्दों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकों" के उप-बंधों से मुक्त किया जाये।

चौधरी बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, आज के एजेंडा में म्युनिसिपल बिल और प्राइवेट कालेजिज (सिक्वोरिटी आफ सर्विस) बिल दोनों बड़े एग्जाहस्टिव बिल है। म्युनिसिपल बिल में तो कम से कम 40 सैक इंक्वाल्ड है। स्पीकर साहब, टाईम का बढ़ाना या न बढ़ाना यह तो एक अलग सवाल है लेकिन मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि म्युनिसिपल बिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है, इसमें मेजर अमेंडमेंट की जा रही है, इसलिये.....

.....

श्री अध्यक्ष: यह तो जब बिल आयेगा, उस वक्त आप प्वायंट रेज करना। उस वक्त आप यह प्वायंट रेज कर सकते है। आज की सिटिंग के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का फैसला है, जिसके बारे में मंत्री महोदय अपना प्रस्ताव पेश कर चुके है और हाउस उसे एडाप्ट करने वाला है। जो भी फैसला हाउस करेगा, उसी के मुताबिक हाउस चलेगा। (विघ्न)

श्री भाम ेर सिंह: बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जहां तक मुझ ख्याल है यह फैसला हुआ था कि केवल म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल आज के दिन डिस्कस होगा, दूसरे बिल नहीं। I am subject to correction. दूसरे बिल जो आज के एजेंडा पर है, वे बाद में आये है, इसलिए उस मीटिंग में उनके बारे में कोई जिक नहीं था।

Mr. Speaker: I will refer you to the minutes of the Business Advisory Committee. It mentioned 'Any other business/legislative bills'

श्री भाम ेर सिंह: स्पीकर साहब, म्युनिसिपल बिल के बारे में बात हुई थी यह जो दूसरे बिल लाये जा रहे है, ये बाद में आये है।

Mr. Speaker: I seem to remember that Jain Sahib had mentioned about it.

श्री भाम ेर सिंह: स्पीकर साहब, यह जो दूसरे बिल लाये जा रहे है, इनके बारे में उस मीटिंग में कोई जिक नहीं आया था।

Mr. Speaker: But it was quite clearly said that any other Government business that the Speaker might admit would also be taken up.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, टैक्स इन बिल लाया गया है, इसके ऊपर डिस्क इन के लिये पूरा मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: टैक्स के बारे में तो बोलने के आपको बहुत ज्यादा मौके मिले थे। मेरे ख्याल में पिछले दस सालों में विपक्ष के सदस्यों को इतना टाईम कभी नहीं मिला, जितना बोलने का इस बार मिला है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, इन्होंने यह कहा था कि फरीदाबाद के कारखानेदारों पर इसी सै इन में टैक्स लगाये जायेंगे। एक अ योरन्स दिया गया था कि इसी सै इन में हम इन कारखानेदारों पर टैक्स लगायेंगे।.....

.....

आबकारी तथा कराधान मंत्री(चौधरी भोर सिंह): फरीदाबाद में कारखानेदारों पर जो टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, हमने इस बारे में बिल बना दिया है। उसके लिये प्रेजीडेंट साहब की मंजूरी की आवश्यकता है, (व्यवधान एवं भाोर)

श्री मांगे राम गुप्ता: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मेरी दरखास्त यह है कि जो आपने यहां पर यह बताया कि 'एनी अदर बिजनैस' भी इसमें शामिल है। 'एनी अदर बिजनैस' और एक्ट बनाने में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है।

श्री अध्यक्ष: आपका कहना यह है कि इसमें बिल कवर्ड नहीं है? यह ठीक नहीं है। एनी अदर बिजनैस में बिल भी कवर हो जाते हैं।

चौधरी बीरेंद्र सिंह: वहां पर कहा गया था 'Any other legislative business'. इसका मतलब यह नहीं कि फ्रै 1 बिल भी लाकर हाउस के सामने रख दिये जायें और डिस्कान का पूरा मौका न मिले।

Mr. Speaker: 'Any other legislative business' में बिल आ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि फ्रै 1 बिल नहीं आ सकता। मैं हाउस की इंफर्मेसन के लिये, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने जो 30 मार्च, 1979 के लिये बिजनैस डिसाईड किया था, वह पढ़ देता हूँ। It is as under-

“Friday, the 30th March, 1979, at 9.30 A.M.

1. Question Hour.
2. Motion under rule 15 regarding non-stop sitting.
3. Motion under rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.
4. The Haryana Municipal(Amendment)Bill, 1979.
5. Any other legislative Bills/Business.

‘Any other legislative Bills/Business’ makes the position rather more clear. I wil now put the motion before the House.”

प्र न है—

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मर्दों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम “सभा की बैठकों” के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

वित्त मंत्री(श्री मूल चंद जैन): मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रिपोर्ट पे ा करना

(i) सबार्डिनेट लैजिसले ान कमेटी की दसवीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Now the Chairman of the Committee on Subordinate Legislation will present the Tenth Report of the Committee.

Chaudhri Harswarup Bura: (Chairman, Committee on Subordinate Legislation): Sir, I beg to present the Tenth Report of the Committee on Subordinate Legislation of the Haryana Vidhan Sabha for the year 1978-79.

(ii) एस्टीमेट्स कमेटी की ग्यारहवीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन कमेटी की ग्यारहवीं रिपोर्ट पे ा करेंगे ।

चौधरी संत कंवर(चेयरमैन ए एस्टीमेट्स कमेटी): मैं वर्ष 1978-79 के लिए आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा के संबंध में बजट अनुमानों पर प्राक्कलन समिति की ग्यारहवीं रिपोर्ट की टाइप की हुई प्रति पे ा करता हूं ।

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 1979

श्री अध्यक्ष: अब लोकल सैल्फ गवर्नमेंट मंत्री बिल पे ा करेंगे ।

स्थानीय भासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): मैं दि हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक, 1979 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि -

दि हरियाणा नगरपालिका (सं तोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि-

दि हरियाणा नगरपालिका (सं तोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये ।

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, यह नगरपालिका सं तोधन विधेयक पढ़ने में बहुत साधारण लगतार है परन्तु इसकी जो रिपरिट है उसके अन्दर झांकने की आवश्यकता है । (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) । उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि सदन के माननीय सदस्य पहले बोल लें और उसके बाद मैं उत्तर दूँ क्योंकि मैं समझता था कि-

कलाम से बेहतर है मेरी खामोशी,

न जाने कितने सवालों की आबरू रूख ली ।

किसी ने अपना सफ़ीना डुबो के साहिल पर,

हजार डूबने वालों की आबरू रख ली ।

डिप्टी स्पीकर साहब, 29 दिन से.....

श्री दीप चंद भाटिया: आन ए प्वांयट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चौधरी राम लाल जी से पूछना चाहता हूँ कि यह भोरो भायरी की जगह है या असैम्बली हाल है?

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर भोर पढ़ने की आज्ञा है। पिछले सालों में यहां पर भोर पढ़े जाते रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले 29 दिन से मैं इस सदन में बैठा हूँ और मैं समझ रहा था कि मेरे विभाग से सदस्य इतने संतुष्ट हैं कि न तो उन्होंने कोई प्रश्न ही पूछा और न ही मेरे विभाग के बारे में कोई बात की। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

श्री मांगे राम गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि किसी एम0एल0ए0 ने मेरे महकमें के बारे में कोई प्रश्न कायम नहीं की। डिप्टी स्पीकर साहब हमने तो सवाल पूछा था लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक भोर और कहना चाहता हूँ—

हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिशें पर दम निकले

बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले।

डिप्टी स्पीकर साहब, वास्तव में यह बिल जो सदन में पेश किया गया है इसके पीछे जो भावना है बिल की क्लोजिंग

पर बोलने से पहले मैं उस भावना को सदन में रखना चाहता हूँ। 1977 के अंदर परम आदरणीय जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हमने प्रजातंत्र को दोबारा स्थापित करने के लिए एक व्रत लिया था। उन्होंने सम्पूर्ण कांति का नारा दिया था और मुझे सदन में यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज के आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल ने इस बिल की स्वीकृति देकर और सदन में इसे पारित करने की आज्ञा देकर प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए एक मिसाल कायम की है। मुझे आशा है कि देश की दूसरी विधान सभाओं के अन्दर भी वहाँ की सरकारें इस प्रकार के बिल लाकर प्रजातंत्र को मजबूत करेंगी। डिप्टी स्पीकर साहब, स्थानीय भासन का मतलब क्या है? मेरे सभी साथियों ने जो सदन में बैठे हैं, बड़ी गम्भीरता से इसका अध्ययन किया है। स्थानीय भासन के ऊपर मैं कुछ न कहते हुए इसके एक प्रोफेसर ने इसके बारे में जो भाव्य कहे हैं, उनको सदन में पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है—

“The affairs of the city are administered by specific regulations framed under the law governing the local bodies. The city like other units of the local Government is a training school of democracy. It is generally said that the working of local government in urban and rural areas is one of our treasured inheritances. The citizens learn at local level how to attend to things and deal with them in a practical way. The Local authority is the proper institution which creates opportunities for intelligent, public spirited and civic minded people to participate in local activities and community

development programmes within the frame work of National policies. The local bodies provide for a training of the citizens in civic matters based upon economic and social planning”.

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के वे भाब्द भी यहां सदन में कहना चाहूंगा जो उन्होंने लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की पहली कांफ्रेस में कहे थे। उन्होंने उस कांफ्रेस में कहा था—

“Local self Government is and must be the basis of any true system of democracy. The democracy may not succeed until it is built on the foundation from below.”

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय न लेता हुआ स्थानीय भासन का जो दूसरा मकसद है उसके बारे में चंद भाब्दों का उल्लेख करूंगा। इसका दूसरा मकसद है—

“The constitution and working of the municipal government affect considerably the routine living and activities of the people in several ways. The local bodies provide the desired amenities for the public and also the day to day services which are essential for the convenience, better standard of living and welfare of the people living in the city. In fact it is the local body if it is well administered which directly concerns the rate payers’ problem and the governments whether provincial or central come later. The intelligent, civic minded persons who are conscious of their duties and responsibilities can prove an asset for improving the work of the services and promoting social and economic development with the administration for completing its task

and meeting the liabilities with success. In order to build up sound and efficient local administration cooperation of the people is a necessity.”

उपाध्यक्ष महोदय, भाहरों की बढ़ती हुई आबादी को व्यवस्थित करना, साथ ही उनकों सहूलियत प्रदान करना और नीचे से डेमोक्रेसी के लिए लोगों को प्रििक्षित करना यह स्थानीय भासन का मुद्दा हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थानीय भासन की नुक्ताचीनी की नियत से या स्थानीय भासन में हुई गलतियों का उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 1972 के बाद इस देा के अन्दर इस प्रकार की मनोवृत्ति पैदा हुई कि भासन का हक केवल विधानसभा या पार्लियामेंट के अन्दर बैठे हुए लोगों को ही और वह भी उन लोगों को है जो उनमें से सरकार में बैठे हुए है। यह बात भी इस देा में कही गई कि जमहूरियत डिरेल हो गई है और हम उसको फिर रेल पर लाना चाहते है। मैं इस देा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने साबित कर दिया कि जनता के अन्दर डेमोक्रेसी डिरेल नहीं हुई थी बल्कि जो कहते थे कि डिरेल हुई है उनको ही जनता ने उखाड़ कर डेमोक्रेसी को फिर रेल पर ला दिया। मैं उसकी व्याख्या न करते हुए हरियाणा के बारे में कहना चाहूंगा। सब से पहले तो मैं सदन के सदस्यों को आपके द्वारा यह बताना चाहूंगा कि किस प्रकार की मनोवृत्ति हरियाणा के अन्दर पैदा की गई। 1973 के अन्दर डेमोक्रेसी का यहां पर जनाजा निकाल कर रख दिया गया। जिला परिशद तोड़ दिये

गये, मार्किट कमेटियों तोड़ दी गई और नोटीफाईड एरिया कमेटीज में नामीने ांज की गई। आज मैं चौधरी देवी लाल को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पंचायतों के चुनाव करवायं, मार्किट कमेटियों के चुनाव करवाने जा रहे हैं और इसी प्रकार से नगरपालिकाओं के भी चुनाव करवाने जा रहे हैं। इसीलिए हमने इस बिल के अन्दर कुछ रेडिकल चेंजिज की है। 1973 के अन्दर 1911 के म्यूनिसिपल एक्ट की धज्जियां उड़ा कर रख दी गई थी। दुनिया के इतिहास में कहीं भी आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि चुने हुए नुमांयदे की बजाये नामिनेटिड लगा दिये जाए। इन्होंने कानून में तरमीम की कि तीन साल तो चुना हुआ नुमांयदा रहेगा और तीन साल एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। तो इस प्रकार की डेमोक्रेसी लिखित रूप में दुनिया के किसी भी कोनें में नहीं मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वह दिन भी याद है जब विरोधी पक्ष के नाते मैंने इसी प्रकार से उस बिल पर खड़े होकर आक्षेप किया था। उस समय मेरी वही स्थिति थी जो आज इन साथियों की है, जो अपोजी ान में बैठे हे.....

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): ऐसी स्थिति कहां थी?

चौधरी राम लाल वधवा: चीफ मिनिस्टर साहब ठीक कह रहे हैं, इनको तो हमने पूर छूट दे रखी है। आज मुझे खु ि है कि जिस चीज का मुझे विरोधी पक्ष में होने के नाते आक्षेप करने का मौका मिला था उसी कमी को दूर करने के लिये आज मुझे यहां पर स्थानीय भासन मंत्री के नाते सौभाग्या प्राप्त हुआ है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इसकी हिस्टरी बताना चाहूंगा.....

.....

श्री सुरेंद्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब, चाहे जितना बोल लें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन आप टाईम नोट कर लें ताकि उसी हिसाब से हमें भी बोलने का टाईम मिल सकें।

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अजीज सुरेंद्र सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि यह बात मैं इसलिये बताना चाहता हूँ कि गैर मुल्की भासक जो इस देा के ऊपर राज करते थे उन्होंने भी यह महसूस किया कि लोगों का जीवन सुधारने के लिये चुने हुए नुमायंदे होने चाहिए। उसका यह परिणाम हुआ कि सब से पहले 1842 के अन्दर बंगाल में पीपलज एक्ट लागू किया गया जिसमें केवल बंगाल प्रान्त को इस किस्म की सुविधा दी गई। उसके बाद यह आवाज और तेज हुई और 1850 में एक एक्ट बना जो बंबई और नार्दन प्रोविंसिज में लागू किया गया। उसके बाद 1873 में कलकता कार्पोरे इन एक्ट बनार जिसे 1876 में, और ज्यादा सहूलियत देने के लिये रिपील किया गया। फिर बम्बई कार्पोरे इन एक्ट बना ताकि देा की जनता में स्थानीय भासन के प्रति जागृति आए। उसके बाद 1911 में आल इंडिया लैवल पर एक एक्ट की बुनियाद रखी गई। हम समझते थे कि उस में बहुत कमियां थी लेकिन 1973 में तो कमाल हो गया। अंग्रेजों ने 1911 के एक्ट के तहत जो सहूलियत या डैमोक्रेटिक राइट्स दिये थे वे आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर लोगों की वोट से

बनी हुई सरकार द्वारा छीन लिये गये। एक्ट में संशोधन करके चुनाव का सिस्टम खत्म कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर ज्यादा न जाते हुए चंद भावों में इस बिल की विवेकशायें बताऊंगा.....

श्री सुरेंद्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आज तो इनके सैक्रेटरी ने इनको खूब तैयार करके भेजा लगता है। (हंसी)

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी पूरी तैयारी के साथ ही बोला करता था। चौधरी सुरेंद्र सिंह उस समय नहीं थे, इनके पिता जी हुआ करते थे। ये अपने पिता जी से इस बारे में पूछ लें कि मैं कितनी तैयारी के साथ बोला करता था।

श्री भामदेव सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आप बिल को देखें कि इसके साथ जो एक्सट्रैक्ट्स हैं ये बिल्कुल डिफैक्टिव हैं। इसलिये इस पर डिस्कशन नहीं चल सकती।

श्री उपाध्यक्ष: आप इनको बोलने दीजिए।

श्री भामदेव सिंह: मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इसके एक्सट्रैक्ट्स डिफैक्टिव हैं इसलिये बोलने का कोई फायदा नहीं है। इस प्वायंट पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि आगे प्रोसीड किया जा सकता है या नहीं। आप इस बिल पर मुलाहिजा करें। इसमें सैकशन 23 जो पेज 5 पर है उसमें लिखा है कि

“After section 100 of the principal Act, the following section shall be inserted,.....’After section 100, section 100A is proposed to be inserted. अब, आप मुलाहिजा करें कि पीछे जो एक्सट्रैक्टस दिये हैं उनमें सैक्शन 100 का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे बिलों पर तब तक डिस्कशन नहीं होती जब तक साथ एक्सट्रैक्टस न हो। इसलिये मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि इसको डैफर किया जाए।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: I can explain it.....

Shri Surrneder Singh: The Minister cannot reply. He is simply the mover of the Bill. The ruling is to come from the Chair.

Development Minister(Thakur Bir Singh): he can explain and clear the point.

Mr. Deputy Speaker: He wants to make the point clear. He may do so.

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्वांयट रेज किया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सैक्शन 100 का एक्सट्रैक्ट देने की आवश्यकता तब होती अगर हम सैक्शन 100 में कोई तबदीली करते। यह तो बताने के लिये है कि सैक्शन 100 के बाद हम सैक्शन 100-ए इनक्लूड कर रहे हैं।

श्री भामदेव सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब.....

श्री उपाध्यक्ष: इन्होंने आपका प्वांयट आफ आर्डर क्लीयर कर दिया है।

चौधरी बीरेंद्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनकी यही एक्सप्लेनेशन है तो सैक 258 से 263 के एक्सट्रैक्ट्स भी अनैक्टिव से ओमित होने चाहिये थे because they are omitting these sections from the Act. But this has not been done and these extracts are given in the Annexure. Similarly section 100 should also have been given in the Annexure and supplied to the members.

श्री उपाध्यक्ष: मिनिस्टर साहब ने क्लीयर कर दिया है कि इसकी जरूरत नहीं है इसलिये मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच जारी रखें।

चौधरी रामलाल वधवा: जो सैक 258 हम बदल नहीं रहे हैं ये वह बतला रहे हैं। हम तो उस सैक्सन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ चंद अहम क्लोजिंग के बारे में पांच मिनट में कह कर अपना स्थान लूंगा। इस बिल के जरिए जो तमाम नोटिफाइड एरिया कमेटीज हैं उनको म्युनिसिपल कमेटीज का नाम दिया जा रहा है और जो पहले नामीनेशन होती थी उसको खत्म करके अब इनके चुनाव कर रहे हैं। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर साहब, हम जो कमेटीयां बनाने जा रहे हैं उनका कोई ला होगा। पिछली सरकार के समय एक भाक्स था जिसकसे कहने से किसी कमेटी को तो रखा जाता था और किसी को

जिसको वह चाहे तोड़ा जाता था। जहां कोई कमेटी टूट गई वहां अलग ही कानून बन जाता था। अब जहां 50 हजार से ज्यादा की आबादी है वहां 'ए' क्लास कमेटी होगी, जहां 20 और 30 हजार के बीच आबादी होगी वहां 'बी' क्लास कमेटी होगी और जहां बीस हजार तक की आबादी होगी वहां 'सी' क्लास कमेटी होगी। अब नोटीफाईड एरिया कमेटीज नहीं रहेगी। अब सभी कमेटियों के चुनाव करवाये जायेंगे।

श्री भाम ोर सिंह: प्वायंट आफ आर्डर सर। आप सैक्शन 100 का मुलाहिजा फर्माएं

'100A. " Revision.-Any person aggrieved by an order passed in appeal under section 99 may, within thirty days of the communication to him of such order, make an application in writing to the State Government for revision....."

उपाध्यक्ष महोदय, जिसके आर्डर के अगेंस्ट अपील की....
.....।

चौधरी राम लाल वधवा: सैक्शन 99 में अपील नहीं है..
.....

श्री उपाध्यक्ष: इसका एक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
That is immaterial.

श्री भाम ोर सिंह: जब हम उस आर्डर के खिलाफ अपील करेंगे तो प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा?

चौधरी राम लाल वधवा: म्यूनिसिपल कमेटी को सस्पेंड रखने की हमने मियाद निश्चित कर दी है। पहले इसकी कोई मियाद नहीं थी, कोई कायदा नहीं था कि कब तक सस्पेंड रखेंगे। हमने इस बात का भी प्रोवीजन कर दिया है कि चुनाव अवधि खत्म होने पर या सुपरसीड होने पर छः महीने के बाद नये चुनाव अवश्य होंगे। उसके बाद विधान सभा चुनाव की तरह चुनाव स्थगित नहीं किये जायेंगे। हमने इन कमेटियों को विधान सभा के बराबर दर्जा दे दिया है। इससे पहले ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं था। मुझे भी 14 साल का अनुभव है। मैं नगर पालिका का सदस्य रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ, एग्जैक्टिव अफसर के तौर पर भी मैंने काम किया है। जो मेरी जिन्दगी में बीती है, वह आपको बताना चाहता हूँ। अगर किसी को मैम्बर, प्रेजीडेंट, वाईस प्रेजीडेंट न रखना हो तो 21 दिन का नोटिस देकर उसको मैम्बरशिप से, वाईस प्रेजीडेंटशिप से, प्रेजीडेंटशिप से हटा दिया जाता था। किन्तु इस बिल में प्रोवीजन किया गया है कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जायेगा जो इन्क्वायरी करेगा। फिर उसके बाद सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही होगी। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, हम ने यह फैसला भी किया है कि राजनैतिक आधार पर किसी नगरपालिका को भंग नहीं किया जाएगा बल्कि जब तक कमेटी को सुपरसीड नहीं किया जायेगा। इसके अलावा हमने ज्यादा लम्बे अरसे तक ये कमेटीज सस्पेंड न रखने का भी प्रोवीजन किया है ताकि ये अच्छे काम कर सकें और जो योजनाएं बनायी हैं उनको पूरा कर सकें। इन नगरपालिकाओं की मियाद

तीन साल की कर दी है। नगरपालिका को इसमें पूरा अख्तियार दिया है। अगर कहीं आग लग जाये या एक्सीडेंट हो जाये तो यह फौरन फायर बिग्रेड को भेज सकती है और उस पर अपना खर्च कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक्ट के तहत अगर कहीं दुर्घटना हो जाती थी तो इन नगरपालिकाओं को डिप्टी कमी नर से इजाजत लेनी पड़ती थी। जब डिप्टी कमी नर मंजूरी दे देता था तभी ये खर्च कर सकती थी। अब ये खुद खर्च कर सकती है और आगे आने वाली कमेटी की मीटिंग में उस खर्च की मंजूरी ले सकती है। इसके अलावा जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि हम बड़े बड़े भाहरों में कार्पोरे न्ज भी बनाने जा रहे है। जैसे रोहतक, फरीदाबाद, अम्बाला और अम्बाला कैंट को मिला कर यमुनानगर और जगाधरी को मिलाकर कार्पोरे न्ज बनाने का प्रोग्राम रखा गया है। इसके अलावा जिस कमेटी की इन्कम एक लाख की हो जायेगी वहां सारे हरियाणा में कार्पोरे न्ज बना दी जायेगी। म्यूनिसिपल कमेटियों को ग्रांट भी दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब ये (अपोजी न्ज वाले) इसलिये नुक्ताचीनी कर रहे है कि तीस साल तक म्यूनिसिपल कमेटियों के एडमिनिस्ट्रे न्ज में जो होता आया है उसे हम बंद कर रहे है। हमें तीस साल बाद दिवालिया हुई सरकार मिली है। इसमें जो गंदगी है पहले हमें यह दूर करनी हैं। इसके सभी रिसोर्सिज खत्म हो चुके थे। अब हम आव यकताओं को देखते हुए पांच साल बाद म्यूनिसिपल कमेटी की ग्रांट रिव्यू करेंगे ताकि कमेटी

प्रगति कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, बाकी बातों को मैं माननीय सदस्यों के बोलने के बाद उत्तर दूंगा।

श्री भाम ार सिंह(नरवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमें इस बात का यकीन था कि मंत्री महोदय बजाये इस बिल को पोलिटिकलाईज करने के, पोलिटिकल भाषण झाड़ने के इस बिल के मुद्दे रखेंगे ताकि मैम्बरज आफ दि हाउस को सारी बातें अवगत हो सकें। लेनिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि को कई बार रिपीट करने से वे समझते हैं भायद हरियाणा के भोले भाले लोग उनकी बात को ठीक मान लेंगे? इन्होंने..... तरीका अख्तियार किया है.....

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने.....बोला है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (व्यवधान) क्या यह भाब्द अनपार्लियामेंटरी नहीं है? मेरी साथी को कहा जाए कि इसको विदड़ा करे। (व्यवधान)

श्री भाम ार सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि ये बार बार कहते हैं कि म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव, कार्पोरे ान्ज के चुनाव भाूगर मिलों में चुनाव करवाने जा रहे हैं और यह बात सुनते सुनते हरियाणा के लोगों

के कान पक गये हैं। मंत्रियों द्वारा यह.....बार—बार रिपिट होता रहा कि चुनाव करवा रहे हैं लेकिन हर बार पोस्टपोन करते रहे। पता नहीं.....कहते हुए इनकोक्यों नहीं आती, तीन बार चुनाव पोस्टपोन हो चुके हैं.....

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब,.....
भाब्द अनपार्लियामेंटरी है, इसको एक्सपंज किया जाए।

डा० मंगल सैन: मेरे साथी बे एक कड़वी आलोचना करें लेकिन यह कहना कि.....है इनको....., ये भाब्द अच्छे टेस्ट में नहीं है। इनको या तो एक्सपंज किया जाए या इन्हे कहें कि वापिस लें। (व्यवधान)

श्री भामोर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे सुनते—सुनते.....आने लगी है और तीन बार इलैक्ट्रान पोस्टपोन कर चुके हैं (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, ये बार—बार मुझे इंटरुप्ट कर रहे हैं और मेरा टाईम जाया कर रहे हैं।

चौधरी रिजक राम: आन ए प्वांयट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, जो भाब्द मेरे दोस्त ने अपने भाषण में इस्तेमाल किये हैं.....और.....ये भाब्द अच्छे टेस्ट में नहीं है। पहले कई बार फैसला हो चुका है कि ऐसे भाब्द अनपार्लियामेंटरी है। आप इन भाब्दों को वापिस करवायें।

श्री उपाध्यक्ष: आप इनको वापिस लें, वरना एक्सपंज कर दिये जाएंगे।

श्री भाम ोर सिंह: भाब्द किस टेस्ट में अनपार्लियामेंटरी है, इस पर आप रूल्ज कंसल्ट कर लें। जिस टेस्ट में मैंने इस्तेमाल किया है उसमें अनपार्लियामेंटरी नहीं है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पिछले डेढ़-दो साल से बार बार म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव स्थगित किये गये। इसलिये स्थगित किये गये है, जैसा कि सब को अच्छी तरह सेपता है कि जनता पार्टी में एक खास घटक है जो म्यूनिसिपल कमेटियों का चुनाव लड़ना चाहता है और यह घटक जानता है कि अगर म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव हो गये तो उनका कोई मैम्बर किसी भी म्यूनिसिपल कमेटी में मैम्बर बन कर नहीं नहीं आयेगा। यही कारण है कि ये चुनाव तीन बार स्थगित किये गये। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल में भी इन्होंने इस बात की गुंजाइ 1 रखी है कि इलैक् इन दो-चार महीने के अन्दर नहीं, बल्कि एक साल के अन्दर करवायेंगे। पेज 2 पर सैक् इन 7 का प्रोवाइजों है, उसमें लिखा है—

“Provided that in the municipalities, specified in the Schedule to this Act, which were of first or second class immediately before the commencement of the Haryana Municipal (Amendment) Act, 1979, the election shall be held within six months of such commencement and elections in the remaining municipalities specified in the said Schedule shall be held within one year of such commencement.....”

डिप्टी स्पीकर साहब, यह बिल जब एक्ट बनेगा तो इस प्रोवीजन के मुताबिक एक साल के अंदर चुनाव करवाये जायेंगे।

पिछले दो साल से तो पहले ही अन-नसैसरी पोस्टपोन करते आये है और इसी तरह तीन साल गुजर जायेंगे, इसके बाद भी पता नहीं चुनाव होंगे या नहीं। दरअसल बात क्या है, क्यों चुनाव नहीं करवाये जा रहे। वधवा साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर्स का जिक्र किया कि पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, वे बे नुमार गड़बड़ियां करते थे, पैसा खाते थे, लगातार एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर काम करते चले आ रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह बात कहना चाहता हूँ कि जनता सरकार और उसके जो लोकल बाडीज के मंत्री है, उन्होंने 13 मार्च को एक गजट नोटिफिके इन अखबार में छपवाया। हरियाणा में जितनी भी नोटिफाईड एरिया कमेटीज है, उनको नोटिफिके इन जारी किया जिसमें लिखा है—

“The Governor of Haryan here by appoints notified areas committees each consisting of one person, specified in column 3 of the said schedule and nominates the persons as shown in column 4 of the said schedule against each committee and further appoints them as Presidents of the respective committees.....’

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इस लिस्ट को गौर से पढ़ें तो मालूम होगर कि ये एप्वायमेंट मैरिट के बेसिज पर, तजुर्बे के बेसिज पर नहीं की गई क्योंकि कमेटियों की हालत सुधारने की इनकी कतई मं ता नहीं है। सारी की सारी एप्वायटमेंटस सियासी

नुक्ता निगाह से पोलिटिकल नुक्तानिगाह से किसी एक घटक को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है।

चौधरी राम लाल वधवा: आन ए प्वांयट आफ आर्डर। इन्होंने बिल्कुल गलत बात कही है और गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। नोटिफाईड एरिया कमेटी के प्रैजिडेंट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर और ऐसा एक्ट में लिखा है। पहले एडमिनिस्ट्रेटर पाट-टाईम लग जाते थे और लगातार चले आते थे, काम भी ठीक नहीं चलता था.....

श्री भाम ार सिंह: यह प्वांयट आफ आर्डर कैसे बना? आप बाद में जवाब दे देना। (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा: पहले जिसकी जो मर्जी होती थी उसको एडमिनिस्ट्रेटर लगा देता था, लेकिन मैंने आर्डर किये हैं कि चीफ सैक्रेटरी साहब से आफिसरज की लिस्ट मंगवा ली जाए और उस लिस्ट के मुताबिक एप्वांयमेंट की जाए। सैक्रेटरी से जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक हमने लगाये हैं, इसमें घटक की कोई बात नहीं है। इनमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो प्राइवेट आदमी हो।

श्री भाम ार सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, बात दरअसल यह नहीं है जो ये कहना चाहते हैं।

Mr. Deputy Speaker: They are Government servants.

श्री भामोर सिंह: वे हमारे भाई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपका जाति तजुर्बा बड़ा रिच है, आप भी सारी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। (व्यवधान) इसी लिस्ट में एक.....का नाम है। यह वह आदमी है जिसको मंत्रिमंडल ने, नरवाना म्यूनिसिपल कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था। इनके खिलाफ इन्क्वायरी पैडिंग है। इन्होंने तीन लाख रुपये की वेइंग मीन खरीदी थी जिसमें घपला किया था और मीन को गलत जगह पर लगा कर कमेटी को पचास हजार रुपये का नुकसान किया था। इनके खिलाफ इन्क्वायरी पैडिंग है और मेरी रिक्वायत पर इनकी ट्रांसफर हुई है। यह पोलिटिकल आदमी है, पोलिटिकल बिनाह पर ही इसको गन्नौर की एन0ए0सी0 का प्रधान बना दिया। यह इनके घटक का आदमी है और इसी तरह की और भी कई मिसालें हैं। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि भीने के महल में बैठकर पत्थर फेंकना बहुत अच्छी बात नहीं है। वधवा साहब जरा अपने गिरेबान में झाँक कर देखें कि उनकी क्या पोजिशन है.....

श्री जयनारायण: आप भी अपने आपको देखें, तीन सिनेमें खोल रखें हैं?

श्री भामोर सिंह: आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आप बगैर परमिशन के बोल रहे हैं। मैं औब्जेक्ट करता हूँ कि ये बगैर परमिशन से न बोलें और मुझे इंटरप्ट न करें। इनका कहने का क्या मतलब है?

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वांयअ आफ आर्डर। अभी अपोजी इन के मेरे एक साथी ने बोलते हुए एक अफसर का नाम लेकर उस पर इल्जाम लगाया है। मेरी गुजारि । यह है कि जो अफसर यहां जवाब न दे सकता हो उसके बारे में बाई नेम यहां इल्जाम नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं आना चाहिये था। He cannot defend himself.

श्री भाम ार सिंह: सरकार डिफैंड करेगी। अगर इस तरह की बात भी हम यहां नहीं कर सकते तब तो हाउस चलाने का कोई फायदा ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे इंस्टांस पर उसकी तबदीली हुई थी। उनके अगेंस्ट अभी इंकवायरी पैडिंग है लेकिन इन्होंने दोबारा उसे वहां लगा दिया।.....
.....(विघ्न)

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, हमार रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस में यह प्रोवाइडिड है कि सबस्टांटिव मो इन के बगैर किसी मंत्री की आलोचना नहीं की जा सकती। इस वक्त म्यूनिसिपल बिल अंडर डिस्क इन है। इस पर बोलते हुए किसी मंत्री के खिलाफ आक्षेप लगाया जान अलाउ नहीं किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य केवल बिल के ऊपर बोलेंगे।

डा० मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी ने बिल्कुल ठीक सुझाव दिया है। इसलिए मंत्री महोदय के बारे में जो बात उन्होंने कही है वह एक्सपंज होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य केवल बिल के ऊपर बोलेंगे।

डा० मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी ने बिल्कुल ठीक सुझाव दिया है। इसलिए मंत्री महोदय के बारे में जो बातें उन्होंने कही है वह एक्सपंज होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने जो बातें बिल के बारे में कही है वे तो ठीक है लेकिन जो बातें मंत्री जी के विरुद्ध कही है वे कार्यवाही में नहीं आएगी।

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब, इसमें कोई सबस्टांटिव मो ान लाने की जरूरत नहीं है।.....
.....

Mr. Deputy Speaker: That will not come on record.

श्री भाम ार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड पर क्यों नहीं आयेगा?

श्री उपाध्यक्ष: आप जो बिल से संबंधित बात कहेंगे वह तो रिकार्ड पर आएगी लेकिन जो मंत्री जी के विरुद्ध बात कहोगे वह रिकार्ड पर नहीं आएगी।

श्री भाम ार सिंह: फिर तो यह बिल पास करने का कोई फायदा नहीं है।.....

डा० मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर है। मेरी एक प्रार्थना है। माननीय सदस्य अगर बैठ जाएं तो मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस सदन की कार्यवाही रूलज के मुताबिक चलती है। रूलज में यह साफ लिखा है कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ किसी ने कुछ कहना हो तो सबस्टांटिव मो इन हाउस में लाए। इसलिए मैं इनसे कहूंगा कि यदि इनके पास मंत्री जी के विरुद्ध कोई मैटीरियल है तो ये हाउस के सामने सबस्टांटिव मो इन लाएं, उस पर बोलें और उसका हम भी इनको करारा जवाब देंगे। अगर इस तरह से ये आउट आफ दि वे जाकर के हिट करेंगे तो इसे हम बरदा त नहीं करेंगे।

श्री भाम ार सिंह: आप में सुनने का सब्र ही नहीं। (विघ्न) आप जानते हैं कि हम आपके गुनाहों का पर्दा खोलेंगे इसलिए इनको बोलने ना दो। (ार)

डा० मंगल सैन: हम भी आपके गुनाहों का पर्दा खोल सकते हैं लेकिन गलत तरीके से नहीं। (ार)

Mr. Deputy Speaker: Before you conclude, I will invite your attention to Rule 100(2), which reads-

“A member while speaking shall not-

.....

(iii) utter treasonable, seditious, defamatory or offensive words;..”

So, kindly be confined to the bill under discussion and also try to wind up.

Shri Shamsheer Singh: Kindly hear me. I am only stating the factual position.....

श्री उपाध्यक्ष: यह बात बहुत हो चुकी है। अब आप इससे आगे चले।

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती डा० कमला वर्मा): डिप्टी स्पीकर साहब, यह चर्चा यहां कई बार हो चुकी है और यह निर्णय भी हो चुका है कि इस तरह से किसी मंत्री को इन्वाल्व नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: मैं यह बात इनसे पहले ही कह चुका हूं।

चौधरी रिजक राम: उपाध्यक्ष महोदय, जो रूल आपने अभी पढ़ कर सुनाया है इसके अलावा एक दूसरा रूल भी है कि बिना सबस्टांटिव मोशन के किसी मिनिस्टर के विरुद्ध डिस्कशन नहीं हो सकती।

Mr. Deputy Speaker: That is there.

श्री भाम ार सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे पता है कि चौधरी साहब की आजकल मंत्री महोदय से बड़ी दोस्ती है और दोस्त को डिफेंड करना ही चाहिए। (विधन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि पिछले सै ान में मंत्री महोदय ने यह आ वासन दिया था कि प्रौपर्टी टैक्स का जो प्रोविजन है उसको एबोलि ा करेंगे। एक महीने तक यह सै ान चला है लेकिन उस आ वासन के मुताबिक एक भाब्द भी इन्होंने यहां नहीं कहा है जोकि बहुत बुरी बात है। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा फरमायेंगे कि म्यूनिसिपल सर्विसिज को प्रोविंि ायसलाइज करने का कोई प्रोविजन ये लेकिन नहीं आए है जो कि एक महत्वपूर्ण बात थी। उपाध्यक्ष महोदय, अगर म्यूनिसिपल कमेटीज से कुरप् ान खत्म करनी है, वैस्टिड इंट्रैस्टस को खत्म करना है तो उन आदमियों को, जो अपने भाहरों में 20-20, 30-30 साल से नौकरी करते है, उनको म्यूनिसिपल सर्विसिज को प्रोविंि ायलाइज करके, वहां से तबदील करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री भाम ार सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, इसी बिल में म्यूनिसिपल कमेटीज की क्लासिफिके ान दी गई है। यह बहुत गलत है क्योंकि यह मोटिवेटिड है। सब सैक् ान 2(ए), क्लाज 3 में लिखा है कि जिन म्यूनिसिपल कमेटीज की आबादी 50 हजार है

या उससे ऊपर होगी उन्हें 'ए' क्लास बनाया जाएगा, बीस हजार से ऊपर आबादी वाली म्यूनिसिपैलेटीज को 'बी' क्लास बनाया जाएगा और बीस हजार से कम आबादी वाली म्यूनिसिपैलेटीज को 'सी' क्लास बनाया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, दो कैटेगरीज के लिए तो इन्होंने कम लिमिट दे दी लेकिन तीसरी कैटेगरी के लिए ऊपर लिमिट देकर एक लकूना छोड़ दिया है। यह गवर्नमेंट की मर्जी है कि जिस कमेटी को यह चाहे 'ए' क्लास बना दे, जिसको चाहे 'बी' क्लास बना दे और जिसको चाहे 'सी' क्लास बना दे। हमें खतरा है कि सियासी तौर पर ये इस प्रोविजन को मिसयूज कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठिए।

मास्टर रिाव प्रसाद(अम्बाला भाहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक दो मिनट बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसमें कोई भाक नहीं कि कांग्रेस राज के अन्दर म्यूनिसिपल कमेटीज को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते थे कि जो कमेटी अपने अधिकार में नहीं हो सकती उसको कैसे खत्म किया जाए। मैं इसकी एक दो मिसालें आपको देना चाहता हूँ। अम्बाला भाहर की म्यूनिसिपल कमेटी पर बहुत अर्से से अपोजीशन का कब्जा रहा लेकिन 1967 के जनरल इलैक्ट्रान से पहले उस समय की कांग्रेस सरकार ने उस म्यूनिसिपल कमेटी को इसलिए तोड़ दिया कि उसके मैम्बर और प्रैजिडेंट भाहर को गंदा रख रहे हैं। अन्दाज लगाइए, 1967 से लेकर 1977 तक वह

यूँ कि यूँ रही। दस साल तक इन्होंने आंख तक नहीं खोली कि उसके चुनाव को दोबारा कराया जाए। इसी तरह का एक उदाहरण मैं सन् 1964 का देना चाहता हूँ। 1964 में म्यूनिसिपल (12.00) कमेटी के प्रैजीडेंट का चुनाव होना था। उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी की हकूमत थी। म्यूनिसिपल कमेटी के एक मैम्बर को नोटिस दे दिया गया कि क्यों न आपको सदस्यता से हटा दिया जाये? प्रैजीडेंट के चुनाव से 10-15 दिन पहले उसको नोटिस दिया गया ताकि मनमाने ढंग से म्यूनिसिपल कमेटी पर अधिकार कर सकें। इस प्रकार की वे धांधलेबाजी को 'सी' क्लास म्यूनिसिपल कमेटीज बना दिया है। चौधरी देवी लाल ने और उसके मंत्रिमंडल ने जनता के अधिकारों को वापिस दिलवाने के लिये यह कदम उठाया है। जिन नगरों की आबादी 20,000 से कम है, उनको 'सी' क्लास बना दिया गया है और जिनकी आबादी 20,000 से ऊपर है और 50,000 से कम है, उनको 'बी' क्लास और 50,000 से ऊपर वाली आबादी को 'ए' क्लास बनाया गया है। जिस ढंग से ये मनमानी कर रहे थे, वह अब नहीं कर पायेंगे। अब कांग्रेस वालों को वह समय स्वप्न में याद आ रहा है। इसलिए उस समय को भूल जाना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, यह सब इररैलेवैंट बातें कर रहे हैं।

श्री मूल चंद मंगला(पलवल): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो म्यूनिसिपल बिल हाउस के सामने आया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्रिंसिपल एक्ट की सैक्शन 91 में यह एड किया जा रहा है—

‘Provided that no persons shall be prosecuted unless he fails to pay such composition fee, not exceeding ten times the octroi due.....’

सैक्टेरी को इसमें यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई टर्मिनल टैक्स पे नहीं करता है तो उस पर दस गुणा जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन इसी बिल की क्लॉज 25, सैक्शन 244 में सैक्टेरी को यह अधिकार नहीं कि वह पांच रूपये भी जुर्माना कर सके। अब यह दोनों बातें कंट्राडिक्टरी है। इसलिये इन दोनों बातों को क्लैरीफाई किया जाये। इन बातों के सिवाय और सब बातें इस बिल में ठीक है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ क्योंकि पहले जो जनता के अधिकार छीन रखे थे, वे अब वापिस दिला दिये गये हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता(जींद): डिप्टी स्पीकर साहब, जो नगरपालिका (अमेंडमेंट) बिल सरकार हाउस के सामने लायी है, उसके ऊपर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। मंत्री जी ने फरमाया है कि कमेटी के इलैक्शन समय पर करवाये जायेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इलैक्शन का टाईम था वह पहले से ही तीन साल था,

लेकिन इस बिल में अब भी यह गुंजाइश है कि यह पीरियड बढ़ सकता है। इसमें यह बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये आम गरीब लोगों की तकलीफें सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ। हाउस टैक्स के बारे में मैंने पिछले दफा भी जिक्र किया था कि हाउस टैक्स के साथ-साथ प्रोपर्टी टैक्स भी लगा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगली दफा इसका बिल ले आयेंगे लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। प्रोपर्टी टैक्स भी नहीं हटा है, हाउस टैक्स भी अभी तक लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि टाइम कम होने की वजह से इस सेशन में हम वह बिल नहीं ला सकें हैं। इसलिये मेरी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस बारे में अमेंडमेंट की जाये। दूसरी चीज जो कालोनियां म्यूनिसिपल कमिटी एरिया में बनी हुई है, जिनमें सड़क, बिजली और पानी की कोई सहूलियत नहीं है, उनसे अगर टैक्स लिया जाता है, तो यह कोई न्यायसंगत बात नहीं कि उनको यह सुविधाएं न दी जायें। सरकार को यह अमेंडमेंट जरूर लानी चाहिए कि जब तक कमिटी उनको सारी सहूलियतें प्रदान न कर दे तब तक हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए। एक दुकान पर बोर्ड के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था जिस आदमी ने अपनी दुकान के सामने कोई बोर्ड लगा रखा है, म्यूनिसिपल कमिटी उससे पैसे चार्ज करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि म्यूनिसिपल कमिटी को क्या तकलीफ है और उससे टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है? गलत तरीके से नोटिस दिये बिना ही उनको चालान कर दिया

जाता है और उनको परे पान किया जाता है। अगर किसी आदमी ने म्यूनिसिपल एरिया में बोर्ड लगा रखा है तो यह टैक्स नहीं लगना चाहिए। एक बात मैंने हाउस में पिछली दफा भी कही थी और मंत्री जी ने यह विवास दिलाया था कि म्यूनिसिपल कमेटीज की जो कौमन लैंड है, अगर उसको किसी पब्लिक इंस्ट्रूमेंट में लिया जायेगा तो उसकी ओपन आर्वाइज होगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि कानून के जरिये कोई अमेंडमेंट लाई जाये ताकि कौमन लैंड बिना आर्वाइज के न बिक सकें। इस अमेंडमेंट में यह होना चाहिए कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर या प्रैजिडेंट बिना आर्वाइज के कौमन लैंड को न बेच सकें क्योंकि वे इस ओर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं। सैंकड़ों रूपये गज की जमीन को 10-15 रूपये गज के हिसाब से दे देते हैं। यह बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए।

जो कालोनियां म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया में ही 20-20 सालों से बनी हुई हैं, उनमें पानी, सड़कों या पक्की गली की सुविधा नहीं है। भाहर के बाहर ये मकान गांवों से आकर किसी मुलाजिम ने या किसी अफसर ने इसलिए बनाए कि भाहर में उनको जगह नहीं मिली। लेकिन म्यूनिसिपल कमेटियां इनकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं देती। जब ये म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया में हैं और इनसे हाउस टैक्स भी वसूल किया जाता है, तो इनको न पक्की गलियों की सुविधा है, न सड़कों की सुविधा है और न ही पानी वगैरह की कोई सुविधा है। यह सब प्रबंध वहां

पर किया जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सबसे जरूरी इस बात को समझता हूँ कि हाउस में यह अमेंडमेंट लाई जाये कि जितनी भी भाहर के बाहर कालोनियां है, उनके अन्दर गलियों को पक्का बनाया जाये, बिजली दी जाये, और अगर पानी का वहां पर निकास नहीं है तो पानी के निकास का भी प्रबंध किया जाये।

श्री देवी दास(सोनीपत): डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो बिल हाउस के सामने पे 1 किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सन् 1973 में म्यूनिसिपल एक्ट में जो अमेंडमेंट की गयी थी कि कमेटी में तीन साल तक प्रैजिडेंट रहेगा और तीन साल तक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, उसको जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया है। सरकार जो कमेटी के चुनाव के बारे में अमेंडमेंट लाई है, यह बहुत अच्छी है, इसकी मैं तार्ईद करता हूँ। दूसरी बात मैं सोनीपत म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। सोनीपत की म्यूनिसिपल कमेटी की हालत बहुत खराब है। मैं मंत्री महोदय से तथा गवर्नमेंट से यह निवेदन करूंगा कि वहां पर सीवरेज सिस्टम चालू किया जाये। दूसरे वहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल की तार्ईद करते हुए सरकार को बधाई देता हूँ कि वह इतनी अच्छी अमेंडमेंट लाई है।

डा० बृज मोहन गुप्ता(जगाधरी): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बिल हाउस के सामने पे 1 है, मैं इसकी तार्ईद करने के

लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं एक अंग्रेजी की फ्रेज पढ़ना चाहता हूँ कि Justice delayed is justice denied. इसके साथ ही एक फारसी की भी मालूम कहवावत है कि 'देर आय दरूस्त आयद' यह बिल लाने में जरा देरी जरूर हुई है लेकिन जो कुछ भी हो गया है, यह ठीक हो गया है। 1973 से लेकर आज तक इन म्यूनिसिपल कमिटीज में धांधलेबाजी हो रही थी। पिछले छः साल तक इनको कोई पूछने वाला नहीं था। जगाधरी की बाबत मैं आपको बताऊँ वहाँ पर तो पिछले डेढ़-दो साल पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर लगा था। इससे पहले वहाँ के एस0डी0एम0 को ही पार्ट टाईम एडमिनिस्ट्रेटर बना रखा था जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत धांधली थी। यह जो बिल लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ और इसका समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है कि—

दि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा।

क्लोज 2

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है—

कि कलाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 3

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाजिज 4 से 6

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाजिज 4 से 6 बिल का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 7

चौधरी बीरेंद्र सिंह(उचाना कलां): डिप्टी स्पीकर साहब, कलाज 7 के अन्दर दो कैटेगरीज बनाई गयी है एक तो है 'ए' और दूसरी है 'बी' । दो साल तक ये चुनाव की बात करते रहे लेकिन इसमें जो प्रोविजन किया है, इसके मुताबिक मुझे तो अगले 5 साल तक भी चुनाव होने की उम्मीद नजर नहीं आती । जो 'ए' और 'बी' कैटेगरी की म्यूनिसिपल कमेटियां है, उनमें चुनाव करवाने के लिये 6 महीने का समय निर्धारित किया गया है कि छः महीने तक

चुनाव करवा दिये जायेंगे। आप देखियें 'सी' कैटेगरी की म्यूनिसिपल कमेटियों में चुनाव करवाने के लिये एक साल की मियाद रखी गयी है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप को पता है कि 'सी' कैटेगरी की म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव तीन महीने के अन्दर-अन्दर हो सकते हैं तो इस तरह से डैलीब्रेटली इलैक्शन को अवायड किया गया है।

स्थानीय भासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): मैं इनकी नौलेज के लिये यह बता देना चाहता हूँ कि जो नोटिफाईड एरिया कमेटीज है, वे पहले म्यूनिसिपल कमेटीज में कंवर्ट की जायेंगी। उसके बाद वार्ड-बन्दी के नोटिफिकेशन होंगे। फिर उसके बाद नये सिरे से वोटर्ज लिस्टें तैयार होंगी। फिर उसके बाद 110 दिन चुनाव के लिये भी तो देने पड़ेंगे।

चौधरी बीरेंद्र सिंह: इस बिल ने आपने यह प्रोवाइजो भी तो लगा दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर लैजिस्लेटिव असैम्बली यह रेजोल्यूशन पास करके रिक्मैण्ड करे कि छः महीने तक यह मियाद बढ़ाई जाये तो यह मियाद बढ़ाई जा सकती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे कोई वजह ऐसी नजर नहीं आती कि जनता पार्टी के लोग एक तरफ तो यह कहें कि हम प्रजातांत्रिक ढांचे में विवास रखते हैं और उसे स्थापित करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा प्रावधान करें कि अगर विधान सभा चाहे तो 6 महीने के लिये इलैक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं। मैं यह कहता हूँ कि ऐसा प्रोविजन करना बिल्कुल अन-डैमोक्रेटिक है। एक

प्रोवाइजों इन्होंने और लगाया है, वह यह है कि ऐसा प्रोवीजन करना बिल्कुल अन-डैमोक्रेटिक है। एक प्रोवाइजों इन्होंने और लगाया है, वह यह है कि अगर विधान सभा के या पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हों तो यह इलैक्ट्रान नहीं होंगे। इस से साफ जाहिर होता है कि ये कमेटियों में चुनाव कराने का इरादा यह सरकार नहीं रखती और इसे लोकतंत्र की बहाली में कोई विवास नहीं है। मैं यह कहता हूँ कि ये तीनों प्रोवाइजों डिलीट होने चाहिएं। इस बिल के अन्दर इस बात के लिये क्लीयर डैड लाईन फिक्स होनी चाहिये कि छः महीने के अंदर या चार महीने के अंदर चुनाव अवय होंगे। अगर आप इस बिल को इसी तरह से रहने देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने दो साल तक तो चुनाव कराये नहीं, आगे छः महीने तक और चुनाव नहीं कराओगे।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि क्लोज 7 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाजिज 8 से 12

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि क्लोजिज 8 से 12 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कलाजिज 13 से 16

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाजिज 13 से 16 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कलाजिज 17 व 18

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाजिज 17 व 18 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कलाज 19

चौधरी बीरेंद्र सिंह(उचाना कलां): डिप्टी स्पीकर साहब, सैक न 68 में सैक न 68-ए ऐड किया गया है। इस नए सैक न में यह है कि हर पांच साल के बाद एक म्यूनिसिपल ग्रांटस कमि न मुकरर किया जाएगा और इसमें पांच आदमी होंगे। एक फाइनेंशियल ऐक्सपर्ट, एक गवर्नमेंट आफिसर, किसी एक कमेटी का प्रैजिडेंट और दो आदमी होंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें फाइनेंशियल ऐक्सपर्ट होने की बात तो कही गई है लेकिन उसकी डेफिनी न नहीं दी गई है। क्या वह कोई अर्थ गारंटी होगा या गवर्नमेंट का सैक्रेटरी होगा, इसकी कोई ऐक्सप्लेने न नहीं दी गई है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा विचार

है कि जो भाहरों से ताल्लुक रखते है या जो लेजिस्लेटिव असैम्बली के मैम्बर है और भाहरों का प्रतिनिधित्व करते है उनके भी एक या दो आदमी इस म्यूनिसिपल ग्रांटस कमिशन के सदस्य होने चाहिएं ।

चौधरी लाल सिंह(नारायणगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे तो इस बिल का सब ने समर्थन कर दिया है और मैं भी समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ लेकिन मेरा कहना यह है कि जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है वह तो आटोमैटिकली म्यूनिसिपल कमेटी बन जाएगी लेकिन जहां की आबादी नोटिफाइड एरिया कमेटी से दोगुनी है और उसको कांग्रेस राज्य ने गंद फ़ैलाकर पंचायत रखा हुआ था उसका क्या होगा?

श्री मांगे राम गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी लाल सिंह बार—बार कांग्रेस की बुराई कर रहे है इनसे पूछिए कि ये कितनी बार कांग्रेस के मैम्बर बनकर आए है?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है—

कि क्लोज 19 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लोजिज 20 से 30

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है—

कि कलाजिज 20 से 30 बिल का पार्ट बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 31

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाज 31 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

ि ाड्यूल

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 1

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि अनेंकिटंग फार्मूला बिल का अनेंकिटंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानीय भासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधावा): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

दि हरियाणा नगरपालिका (सं तोधन) विधेयक पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि हरियाणा नगरपालिका (सं तोधन) विधेयक पास किया जाए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूँ। आनरेबल मिनिस्टर ने पब्लिक में और प्रैस कांफ्रेंस में खड़े होकर कहा था कि म्यूनिसिपल कमेटीज के मुलाजिमों की सर्विस को ऐफिं एंट बनाने के लिए उनका स्टेट कैडर बनाया जाएगा और इन को ट्रांसफरेबल बनाया जाएगा क्योंकि एक-एक आदमी को एक ही भाहर में पच्चीस तीस साल सर्विस करते हो गए हैं। वे लोग अच्छा काम नहीं करते।

इसलिए इन पोस्टों को भीघ्र ट्रांसफरेबल बनाया जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन देहातों की आबादी पांच हजार है उनको वही फ़ैसिलिटीज दी जाएं जो भाहरों को मिलती है। तीसरी बात यह है कि भाहरों को जो आमदनी होती है वह देहात और गांव से होती है। देहात के लोग अनाज, डंगर और बहुत सी चीजें लेकर आते हैं और इस प्रकार से आधे से ज्यादा पैसा देहात से आता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वह पैसा देहात पर खर्च होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए जैसा कि पिछले दिनों किया गया कि दस लाख रूपया सिरसा म्यूनिसिपल कमेटी को दे दिया तथा कई और म्यूनिसिपल कमेटीज को दे दिया। कैथल म्यूनिसिपल कमेटी की हालत बहुत खराब है। उस कमेटी को 'ए' क्लास कमेटी बनाना चाहिए और उसको दस लाख रूपया देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, जो म्यूनिसिपल एक्ट बनाया गया है उसको सरकार खुद ही से बनाए हमें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन मेरा कहना तो यही है कि भाहरों में जो पैसा आता है वह देहात से आता है उसका कम से कम आधा पैसा देहात में लगना चाहिए।

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने दो तीन प्रश्न उठाए हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि हम इन सर्विसिज को प्रोविन्सलाइज्ड कर रहे हैं। एक्ट में आलरेडी इसका प्रोवीजन है और हम इसके बारे में सर्विस रूलज बना रहे हैं इससे बहुत सी सर्विसिज प्रोविन्सलाइज्ड हो

जाएंगी। जो जनरल ट्रांसफर होंगे उनमें इनके भी ट्रांसफर होंगे। दूसरी बात इन्होंने कैथल को 'ए' क्लास म्युनिसिपल कमेटी बनाने के लिए कही है। इन्होंने डिप्टी साहब को पढ़ा नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी साहब में जो 'ए' क्लास म्युनिसिपल कमेटीज है उनमें कैथल का नाम है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भाहरों को जो आमदनी होती है वह देहात से चीजें आती है जैसे अनाज है, डंगर है, उनसे होती है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि मैंने सब्जी, चारा और भूसे पर से महसूल खत्म कर दिया है। पहले अर्बन एरिया में मवे टैक्स लगता था अब सारे हरियाणा के अन्दर इसको खत्म कर दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हाउस टैक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। भाहरों के अन्दर पचास परसेंट आबादी देहात की होती है जैसे हरिजन है, रिक् के वाले है, स्टूडेंट्स है और गवर्नमेंट एम्पलाइज है उनको हमने हाउस टैक्स में सहूलियत दी है। कांग्रेस के जमाने में यह था कि जिस मकान का किराया दस रूपए महीना था वह हाउस टैक्स से माफ था। मैंने इसको बढ़ाकर छः सौ रूपया सालाना कर दिया है और इस तरह से भाहर की एक तिहाई आबादी जो गांव की थी और गरीब थी उनके ऊपर से हाउस टैक्स माफ हो गया है। मैंने हाउस टैक्स के बारे में गाइड लाइज दी है कि इस हिसाब से हाउस टैक्स लगाया जाए और अब उसी हिसाब से लगाया जा रहा है। अब हरिजन, रिक् के वाले, स्टूडेंट्स तथा दूसरे गरीब लोगों को काफी राहत मिलेगी।

श्री मांगे राम गुप्ता(जींद): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि एक्ट के मुताबिक अब हाउस टैक्स लगाया जाएगा। मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि कानून के मुताबिक जो किराए की लेटैस्ट असैस्मेंट है उससे पच्चीस परसेंट से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं की जा सकती लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैक्सिमम केसिज में दो सौ परसेंट एक्ससैस बढ़ाव की है।

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गाइड लाइज भेज दी है लेकिन क्योंकि ला के नीचे यह म्यूनिसिपल कमेटी की ही पावर है और गवर्नमेंट उसमें दखल नहीं दे सकती। फिर भी जो गाइड लाइज मैंने भेजी है अगर उसके अगेंस्ट कोई केस हुआ है तो मेरे नोटिस में लाएं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह तो वही बात है कि—

ए कब्रस्तां टूटती क्यों नहीं खामोशी तेरी,

हम तो मर-मर कर मुझे आबाद किये जाते हैं।

डा० बृज मोहन गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, एमरजेंसी के अन्दर हाउस टैक्स बीस गुना बढ़ा दिया गया था और किसी की सुनवाई नहीं होती थी। अगर कोई कहने गया तो उसको 'मीसा' में बंद कर दिया गया।

चौधरी शिव राम वर्मा(नीलोखेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बिल में कोई ऐसी बात

नहीं है। जितनी पहली कमियां थीं वे सारी दूर कर दी गई हैं। मैं समझता हूँ कि आवकता के मुताबिक यह बिल बनाया गया है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। राम लाल जी मेरे साथी हैं और मैं इनकी भावनाओं को जानता हूँ। मैंने इस बारे में कहना तो और भी था लेकिन समय नहीं है। पहले एक्ट में यह था कि कमेटी के चुनाव हो जाते थे और रिजल्ट आउट हो जाता था। परन्तु इस संबंध में जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता था तब तक कमेटी काम नहीं कर सकती थी लेकिन इस बिल में अब यह कर दिया गया है कि रिजल्ट निकलने के तीस दिन के अन्दर-अन्दर अगर नोटिफिकेशन नहीं भी होता है तो भी नोटिफिकेशन हुआ माना जाएगा और कमेटी अपना काम भुरु कर सकेगी। तो यह कोई छोटी बात नहीं है जो इस बिल में की गई है। पहले जो डिले की जाती थी वह बंद हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है कि—

दि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 1979

आबकारी तथा कराधान मंत्री(श्री भोर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा साधारण विधेयक (संशोधन) विधेयक, 1979 सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

में यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि—

दि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं गोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं गोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है कि—

दि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं गोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि क्लोज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाजिज 3 से 6

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाजिज 3 से 6 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 7

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाज 7 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 1

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनेकिटिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि अनेकिटिंग फार्मूला बिल का अनेकिटिंग फार्मूला हो

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आबकारी तथा कराधान मंत्री(श्री भोर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

दि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं गोधान) विधेयक पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं गोधान) विधेयक पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है कि—

दि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं गोधान) विधेयक पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) बिल, 1979

शिक्षा मंत्री(श्री हीरा नंद आर्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा संबंध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक, 1979 सदन में पेश करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि—

दि हरियाणा संबंध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि हरियाणा संबंध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री अध्यक्ष: मुझे इस मोर्दान पर चौधरी रिजक राम जी की ओर से एक अमेंडमेंट की सूचना की प्राप्ति हुई है। चौधरी रिजक राम जी कृपया अपनी अमेंडमेंट पेश करें।

चौधरी रिजक राम(राई): स्पीकर साहब, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूँ कि हरियाणा संबंध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक, 1979 हरियाणा विधान सभा की निम्नलिखित सात सदस्यों की सिलैक्ट कमेटी को इस निर्देश के साथ सौंप दिया जाए कि कमेटी विधान सभा के अगले सत्रान के भुरु होने से पहले अपनी रिपोर्ट पेश कर दे:—

1	शिक्षा मंत्री	चेयरमैन
2	डा० मंगल सैन, उद्योग मंत्री	सदस्य
3	श्री हरस्वरूप बूरा, एम०एल०ए०	सदस्य
4	राव बीरेंद्र सिंह, एम०एल०ए०	सदस्य
5	श्रीमती सुशमा स्वराज, एम०एल०ए०	सदस्य
6	श्रीमती भांति राठी, एम०एल०ए०	सदस्य
7	श्री रिजक राम, एम०एल०ए०	सदस्य
(प्रस्ताव को पेश करने वाले)		

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Affiliated College (Security of Service) Bill, 1979 be referred to the Select Committee of the Haryana Vidhan Sabha, consisting of the following seven members:-

1	Education Minister	Chairman
2	Dr. Mangal Sein, Industries Minister	Member
3	Shri Har Swarup Bura, M.L.A.	“
4	Rao Birender Singh, M.L.A.	“

5	Smt. Sushma Swaraj, M.L.A.	“
6	Smt. Shanti Rahtee, M.L.A.	“
7	Shri Rizaq Ram, M.L.A.(the mover of the motion)	“

with the direction that the Committee to submit its report before the commencement of the next Session of the Vidhan Sabha.

साहेबान, यह प्रस्ताव सदन के सामने रखने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी अर्ज करूंगा कि रूल्ज आफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस इन हरियाणा विधान सभा के रूल 132(2) के तहत यह है—

‘No member shall be appointed to a Select Committee unless he is willing to serve on the Committee. The mover shall ascertain before moving his motion whether members proposed to be included by him in his motion are willing to serve on the Committee. The name of the Deputy Speaker or of a member of the Panel of Chairmen shall not be included in the motion except in consultation with the Speaker.’

यानी कि डिप्टी स्पीकर या किसी चेयरमैन साहेबान का नाम स्पीकर से कंसलटे इन किये बगैर इसमें इनक्लूड नहीं होना चाहिये। तो इसमें सिर्फ इतनी बात है कि चौधरी हरस्वरूप बूरा जो पैनल आफ चेयरमैन में है, उनका नाम इसमें इनक्लूड

है लेकिन इस बारे में मेरे को कंसल्ट नहीं किया गया है। खैर यह बात तो बाद में डिस्कस की जा सकती है।

Shrimati Shushma Swaraj: I have not been consulted at all.

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, कमेटी मैम्बरज की इसमें कोई रिजिडिर्ट नहीं है कि वे मैम्बर हों लेकिन ऐजुके इन मिनिस्टर ऐसी सिलैक्ट कमेटी के आम तौर पर मैम्बर होते हैं। मैं इस संबंध में संतोधान पे आ करना चाहता हूँ, अगर अमेंडमेंट मंजूर हो तो स्पीकर साहब, स्वयं सिलैक्ट कमेटी मुकर्रर कर दें, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौधरी रिजक राम ने कमेटी के 7 मैम्बरों के जो नाम दिये हैं उनमें उनका खुद का नाम भी शामिल है। यह तो वही बात हुई कि गांव इक्ठठा होकर यदि इतेफाक से पंचो और सरपंच का चुनाव करना चाहे तो ऐसा होता है कि किसी गांव के एक व्यक्ति को सालस मुकर्रर कर दिया जाता है और उसको अखित्यार दे दिया जाते हैं कि वह पंचों और सरपंच का नाम रख दें। एक दो मिसालें ऐसी हैं जहां उस व्यक्ति ने स्वयं को सरपंच घोशित कर दिया, यही बात यहां पर भी लागू हो रही है क्योंकि इस कमेटी के मैम्बरों में श्री रिजक राम जी ने अपना नाम भी रख लिया है।

Mr. Speaker: There is nothing in the rules which debars the mover to include his name in the membership of the select committee.

चौधरी रिजक राम: स्पीकर महोदय, मैंने अपना नाम तो इसलिए रखा था कि मैं खुद तो रजामंद था ही (हंसी)। असैम्बली रूल्ज के रूल नं० 132 के सब रूल (3) में भी यह लिखा है—

‘(3) The Minister to whose department a Bill relates, the member-in-charge of the Bill, the Advocate-General, and either the Deputy Speaker or a member of the Panel of Chairman as may be nominated by the Speaker shall be members of every Select Committee; and it shall not be necessary to include their names in any motion for appointment of such a Committee.

तो अंडर दिस रूल ये खुद ब खुद उसके मैम्बर होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो स्पीकर साहब फरमायेंगे वह हमें मंजूर होगा। स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक दो बातें कहना चाहता हूँ। इस बिल में कई ऐसी धाराएँ हैं जिनके बारे में मैं शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। टीचर्स को सिविलियोरिटी मिले यह आज के हालात के मुताबिक आवश्यक भी है और इसमें कोई संदेह की बात भी नहीं है। इस बिल में जहाँ तक क्लॉज 7 का सवाल है जिसमें डिस्मिस के अलावा कोई भी और सजा दी जाए तो उस पर अपील में डीपीआई या सरकार नजरसानी कर ले तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंनेजिंग कमेटी भी उस एम्पलाई को कालेज से हटाना

नहीं चाहेगी। अगर डी०पी०आई० या सरकार उसकी सजा कम कर दे तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा उद्देश्य जो संशोधन लाने का है वह विशेषकर उन हालात में है जब मैनेजिंग कमेटी किसी टीचर को कालेज से निकालना चाहती हो। स्पीकर महोदय, सरकार चल रही है इसमें बहुत से डिपार्टमेंट हैं। एक हैड आफ दि डिपार्टमेंट है। अगर किसी सबोर्डिनेट की उससे नहीं बनती तो वह उस पर एकान्त लेता है। अगर वह रिप्रजेंटेशन देता है तो सरकार का इतना बड़ा अदायरा है कि वह किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन कालेज का एक एम्पलाई या टीचर अगर ऐसे हालात पैदा कर दे जिससे मैनेजमेंट उसको निकालने के लिए मजबूर हो जाए तो उसे निकालने से पहले इस एक्ट के तहत पहले डी०पी०आई० की मंजूरी ली जाएगी कि आया यह सजा दी जाए या नहीं। अगर डी०पी०आई० भी उसकी एप्रूवल दे देता है तो सरकार को यह अख्तियार है कि वह डायरेक्शन दे सकती है कि इस एम्पलाई को रखा जाए। अगर मैनेजमेंट फिर भी उस एम्पलाई को नहीं रखती तो सरकार उस कालेज की ग्रांट बंद कर सकती है, इस बिल में ऐसा ही प्रोवीजन है। मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री को अर्ज करना चाहता हूँ। वे स्वयं इसमें दिलचस्पी भी रखते हैं और इनका तजुर्बा भी है। एक एम्पलाई जो कालेज में ऐसे हालात पैदा कर दे कि मैनेजिंग कमेटी और प्रिंसिपल से उसकी बनाना न सके और उनकी मर्जी के खिलाफ उसको कालेज में रखा जाये तो आप अंदाजा लगाइये कि क्या वहां की शिक्षा अच्छी तरह हो सकती है? स्पीकर साहब, मैं

इस बात के विरुद्ध नहीं हूँ कि टीचर्स को सर्विस सिक्योरिटी न दी जाये या एम्पलाईज को सिक्योरिटी न दी जाये लेकिन देखना यह है कि आया ऐसे हालात तो शिक्षा केंद्रों में पैदा नहीं हो जाएंगे जिनकी वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का माहौल ही खराब हो जाए। यह बात मैं नुक्ताचीनी की बिनाह पर नहीं कर रहा हूँ बल्कि यह हकीकत है कि आजकल जितन भी गवर्नमेंट कालेजिज हरियाणा भर में है उनमें शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। उनके जो सालाना नतीजे आते हैं उनसे हमें बहुत मायूसी होती है। लेकिन कुछ प्राइवेट कालेजिज हैं जिनके नतीजे बहुत अच्छे आते हैं और वहां के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जगहें हासिल करते हैं। तो अगर इन कालेजिज में भी ऐसे हालात होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारे हरियाणा में शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर जाएगा। आप इनको सिक्योरिटी दीजिए लेकिन एजुकेशन की कास्ट पर मत दीजिए। बच्चों की एजुकेशन की कास्ट पर अगर आप इनको सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो आप याद रखें कि हरियाणा में जो थोड़ा बहुत तालीम का मियार आज बचा हुआ है वह भी खत्म हो जाएगा। अगर आप टीचर्स को सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो यह कि जो डिसिप्लिनरी एक्ट्स बनायें, उसमें आप डीपीआई का नाम रखें। जो फैसला हो डीपीआई उसमें शामिल हो। वह वहां तक वातावरण भी देखें। मिसल पर जो बातें आये उनको डीपीआई एग्जामिन करे। यानी उसके सामने जो भाहादत हो, गवाहियां हों

या जो वातावरण हो, उसको देख कर वह जो भी फैसला हो उसको मान लेना चाहिए। अगर ये मामले साल-साल या दो-दो साल तक लटकते रहेगे तो न तो उसकी जगह दूसरा टीचर आएगा और न ही वह खुद ही काम करेगा। इसलिए एजुके ानल इंस्टीचसु ांज में ऐसा वातावरण पैदा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक तो यह तजवीज करना चाहता हूं कि आप बे ाक डिस्पलनरी एक् ान कमेटी में एक या दो नौमीनी सरकार के या डी0पी0आई0 को रख दें या टीचर्ज के जो नुमायदें है उनको रख दें, हमें कोई एतराज नहीं। ऐसा करने से सम्मिलित होकर वे हालात का जायजा ले सकते है। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहता ऐसे-ऐसे भाोचनीय हालात भी टीचर्ज की तरफ से हुए हैं मैनेजिंग कमेटी भी ज्यादाती करती है लेकिन इसका वर्णन करना इस समय मुनासिब नहीं है। अब आपने इस बिल में यह प्रावधान कर दिया है कि वह अपील के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। अपने खिलाफ प्रोपोजड किए गए एक् ान के खिलाफ डायरैक्टर के पास अपील कर सकता है लेकिन कई बार भाहादत पूरी नहीं मिलती, इस बिनाह पर उसको सजा हो जाती है। इधर से अगर सरकार कहे कि उस टीचर को रखो और उधर मैनेजिंग कमेटी कहे कि नहीं रखना है, तो कनफ्लिक्ट हो जाएगा। इस तरह से कालेज का काम नहीं चल सकता। कोर्ट में अपील करने के लिए सरकार की मर्जी के खिलाफ न निकाला जाए तो बिल में ट्रांसफर का प्रोवीजन कर दिया जाए। जिस टीचर को किसी कालेज की मैनेजमेंट निकालना चाहती है, उसकी प्रिंसीपल के साथ अनबन

चल रही है और मैनेजमेंट की मर्जी के खिलाफ सरकार उस टीचर को रखना चाहती है तो इन हालात में कालेज का वातावरण ठीक नहीं रह सकता। अगर टीचर की प्रिंसिपल से अनबन है तो यही अच्छा रहेगा कि उस टीचर की ट्रांसफर किसी दूसरी कालेज में कर दी जाए। लेकिन इस बिल में टीचर को कालेज से बाहर भेजने का कोई प्रोवीजन नहीं है। इसलिए स्पीकर साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस एक्ट में यह प्रोवीजन करा दें कि सरकार इन्टर-ट्रांसफर कर सकती है, इसमें किसी को एतराज नहीं होगा। इससे कालेज का वातावरण भी ठीक रहेगा और सारा मसला भी हल हो जाएगा। आप इनको सर्विस की सिक्योरिटी प्रदान करें लेकिन एजुकेशन की कास्ट पर बिल्कुल न करें। कोई भी कदम जल्दी में न उठाएं और जो तजवीज मैंने रखी है, यह बिल्कुल सही है, सरकार इस पर गौर करे। इस पर सरकार एक कमेटी बना दे। उस कमेटी में सरकार चाहे किसी भी आनरेबल मैम्बर को रखे, किसी को भी अप्वायंट कर दे, किसी को कोई आपति नहीं, लेकिन इस पर विचार जरूर करें। वह कमेटी एक महीने में, दो महीनों में या जो अवधि सरकार मुकर्रर करे, उस के दौरान अपनी रिपोर्ट दे दे। इस वक्त बे तक आप बिल पास कर लें, लेकिन इस बात पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि इसमें बच्चों की तालीम का सवाल है। कहीं ऐसा न हो कि टीचर्ज को सर्विस की सिक्योरिटी देने के जो काम में, शिक्षा का मयार जो पहले ही गिरा हुआ है वह और ज्यादा न गिर जाए। स्पीकर साहब, जो संशोधन मैंने दिया है, मेरे खयाल में सरकार इस पर जरूर विचार

करेगी। मंत्री महोदय आम तौर पर हर समस्या पर गम्भीरता से विचार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस तरमीम पर भी विचार करेंगे।

श्री जगन नाथ(बवानी खेड़ा-अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन में पेश है, यह काफी हद तक ठीक है क्योंकि इस विधेयक से लैक्चररज और टीचर्ज को सर्विसिज की सुरक्षा मिलेगी। हमने अक्सर देखा है कि भिवानी, दादरी और रेवाड़ी के अन्दर जो कालेजिज है, उनमें टीचर्ज के दस्तखत तो 1100 रूपये पर करवाते हैं लेकिन देते हैं सिर्फ 500 रूपया। अगर लैक्चरर मैनेजमेंट की मर्जी के हिसाब से न चले तो उसकी छुट्टी हो जाती है। इस बिल के जरिए उनकी सुरक्षा है लेकिन यह परमानेंट समाधान नहीं है। टीचर्ज की सुरक्षा के लिए जो कुछ आपने बिल में किया है, उसको साईड-ट्रेक करने के लिए मैनेजमेंटस रात-रात में ही कोई न कोई तरीका निकाल लेगी और समाधान की बात उसी वक्त खत्म हो जाएगी। एक ही तरीका है कि तमाम प्राइवेट कालेजिज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए क्योंकि प्राइवेट कालेजिज या स्कूल कोई न कोई न्यूसेंस किएट करते रहते हैं। कहीं जाट कालेज का नारा लगता बैठते हैं, कहीं ब्रहाम्ण कालेज का नारा लगा बैठते हैं। इसका परमानेंट समाधान तब होगा, जब इन सब का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। इन कालेजों को 80 परसेंट अनुदान सरकार देती है, सिर्फ 15 परसेंट की कमी रहती है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस 15 परसेंट की

कमी को भी पूरा करके तमाम कालेजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इसके अलावा जितने भी कालेज या स्कूल जाति के नाम पर चले हुए हैं कोई जाट के नाम पर, कोई अहीर के नाम पर, कोई ब्रह्मण के नाम पर, इन सब के नाम चेंज किए जाने चाहिए...

.....

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, ये अहीरों का नाम ले रहे हैं, अहीरों का नाम कालेजों के साथ रहना चाहिए (व्यवधान) हमारे बगैर तो फौज भी नहीं चल सकती.....
.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो नाम ले रहे हैं वह किसी जाति का नाम नहीं है, कालेज का नाम है।

श्री जगन नाथ:.....
.....(व्यवधान)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू:.....
.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वजारत तो बड़े-बड़े खा बैठे हैं। वक्त की बात है, इसका इससे क्या संबंध है?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि कालेजिज का नाम जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होती है। जहां मैं पढ़ता

था, वहां भी जाति के नाम पर दो कालेज थे। उनका आपस में हर समय तनाव बना रहता था, आपस में पिटाई होती थी। इसलिए जाति के नाम पर कोई कालेज नहीं होना चाहिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम जाति के आधार पर हैं, ये भी नहीं होने चाहिए। इससे एक जाति की दूसरी जाति के प्रति नफरत पैदा होती है, इसी कारण ये सदियों से नफरत के अड्डे बने हुए हैं। एक जाति दूसरी जाति को डौमीनेट करती है। एक जाति अपना प्रचार करती है और दूसरी उसके खिलाफ प्रचार करती है, इस तरह से तनाव बढ़ता रहता है जिसका प्रचार आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, जाति के आधार पर अगर इनकी सीट रिजर्व न होती तो ये कभी एम0एल0ए0 बन कर न आते.....(व्यवधान)

श्री जगन नाथ: मैं तो जनरल पूल से बन कर आया हूँ, रिजर्व सीट से नहीं आया। (व्यवधान) मैं कह रहा था कि प्राइवेट कालेजों का समाधान परमानेंट होना चाहिए। जहां इन कालेजों को 80 फीसदी अनुदान देते हैं, वहां 100 फीसदी कर दें और इनको अपने अंडर ले लें। इन कालेजों का नाम किसी बड़े नेता के नाम पर बे तक हो जाये लेकिन जाति के नाम पर नहीं होना चाहिए, इससे बड़ी नफरत फैलती है। मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरे सुझाव पर गौर करेगी।

चौधरी बीरेंद्र सिंह(उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हाउस में जो डिस्कान चल रही है, क्या यह अमेंडमेंट पर है या सारे बिल पर हो रही है? मुझे बता दें ताकि मैं उसी हिसाब से बात कहूँ।

कई सदस्य: आप दोनों पर ही कह दें। (व्यवधान)

चौधरी बीरेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस बिल की मंता यह है कि प्राइवेट कालेजिज के जो लैक्चरर्ज हैं उनको सर्विस की सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन अभी मेरे माननीय सदस्य चौधरी रिजक राम जी ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा की कौन्सिल पर इनकी सर्विसिज को सिक्योरिटी न दी जाए। स्पीकर साहब, इस बिल में अगर गौर से देखा जाए तो मालूम होगा कि यही कोर्निल की गई है कि सारी की सारी पावर्ज गवर्नमेंट में वैस्ट हो जाएं। यह कहा जाता है कि जनता पार्टी की सरकार यह चाहती है कि हर स्तर पर प्रजातंत्र का ढांचा मजबूत किया जाए। प्रजातंत्र का ढांचा, केवल विधान सभा और पार्लियामेंट में ही मजबूत नहीं होना चाहिए। कुछ और भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं, आग्नेनाइजेण्ड है, जिन में खुद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इनको भी मजबूत किया जाना चाहिए। इन सारी बातों को देखते हुए भी अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट कालेजिज के लैक्चरर्ज को सिविल रिट करने से डिबार कर दिया गया है। स्पीकर साहब, बार-बार जनता पार्टी के लोग एमरजेंसी की दुहाई देते थे, चिल्लाते थे कि एमरजेंसी के दौरान अदालत का गला घोंटा गया लेकिन (13.00

बजे) अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा गला घोंटने वाली कोई बात नहीं हो सकती कि एक अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाता है उसे यदि डी०पी०आई० के दफ्तर से न्याय ने मिले तो वह कानून का दरवाजा भी न खटखटा सके। फैसला तो किसी से भी गलत हो सकता है, डी०पी०आई० से भी हो सकता है और सरकार से भी हो सकता है। इन सारी चीजों को देखते हुए ही तो न्यायालय बनाए जाते हैं। अगर हम कानून में इस तरह का प्रावधान कर देंगे कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी तरक्की रोकी जाती है या उसे नौकरी से निकाला जाता है वह अदालत में नहीं जा सकता तो फिर प्रजातंत्र का क्या फायदा?

श्री हरफूल सिंह: इंदिरा गांधी ने तो दिवारे तोड़ दी थी। आप कैसे इंसफ की बात करते हैं?

चौधरी बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, यह सरकार तो प्रजातंत्र की दुहाई देती है, स्पेसियल कोर्ट्स की दुहाई देती है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस देश की उन्नति की बुलंदी तक पहुंचाया था। हमारी सरकार ने किस तरह से बंगला देश को आजादी हासिल करने में मदद की यह सारे संसार के सामने है।
(गोर)

चौधरी लालू सिंह: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मैं अपने माननीय सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से कहना चाहूंगा कि इस मुल्क के साथ जो अत्याचार इस इंदिरा कांग्रेस ने

किया है उसे यह दे । कभी नहीं भूल सकता लेकिन ये फिर भी उसका नाम लेने लग रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है ।

चौधरी बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं शिक्षा मंत्री जी से पुरजोर सिफारिश करूंगा कि अगर ये इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को नहीं भेजना चाहते तो कम से कम इसमें यह प्रावधान तो जरूर कर दें कि कोई भी आदमी, कोई भी अध्यापक, कोई भी स्टुडेंट, कोई भी मैनेजिंग कमेटी का मैम्बर यदि सरकार के फैसले से संतुष्ट न हो तो उसे कम से कम यह अधिकार जरूर दिया जाए कि वह अदालत में जाए और उससे न्याय की मांग कर सके । यह हर इन्सान का मौलिक अधिकार है । इससे किसी इंसान को वंचित रखना मौलिक अधिकारों की दुहाई देने वाली सरकार को भोभा नहीं देता कि इस किस्म के आर्बिट्रेरी फैसले लिए जाएं और अदालतों के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर दिए जाएं ।
(विध्न)

स्पीकर साहब, क्लोज 11 में स्टेट गवर्नमेंट को वे पावर्ज दे दीर गई है जो किसी एक्ट में देखने को नहीं मिलती । इसी तरह से क्लोज 9 में यह कहा गया है कि जो कार्यवाही गवर्नमेंट का कोई अफसर, की हैसियत से या अपील सुनते वक्त करेगा उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही कहीं नहीं हो सकती । न अपील ही हो सकती है और न ही अदालत में जाया जा सकता

है। अब यह कैसे मान लिया जाए कि हर सरकारी अफसर जो इंकवायरी कंडक्ट करेगा उसका फैसला मैलाफाइडी न हो बल्कि न्यायसंगत हो। यह देखते हुए यह सैक इन भी अनडैमोक्रेटिक है। गवर्नमेंट के आफिसरज को इसमें बेइंतहा भाक्ति दी गई है जिसका मिसयूज होना जरूरी है। यह क्लोज भी इस बिल में से डिलीट की जानी चाहिए। इन भाबदों के साथ मैं चौधरी रिजक राम जी की मो इन का स्वागत करता हूं और यह कहता हूं कि यह बड़ा डैलिकेट क्वेचन है क्योंकि आप ऐप्रिप्रिएट करेंगे कि हरियाणा के 16 साल से 22 साल तक के नौजवान हजारों की संख्या में इन संस्थाओं में शिक्षा पा रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस मामले को सिलैक्ट कमेटी द्वारा निपटाया जाए और फिर सदन में लाया जाए ताकि और फैक्टस लोगों को मिल सकें।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय ने हरियाणा संबंध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक, 1979, आज सदन में पेश करके बहुत सराहनीय कार्य किया है। मैं आज उन्हें इसके लिए बधाई देती हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय, यह वह समस्या है जो पिछले 32 वर्ष से चली आ रही है। आपने देखा होगा कि विधान सभा के अधिवेशन में गाहे-बगाहे इसका जरूर उल्लेख आया है, किसी न किसी सदस्य ने जरूर इस मसले को उठाया है। आज तक यानी 32 वर्ष से प्राइवेट कालेजिज के टीचरज की कोई बात नहीं सुनता था,

मैनेजमेंट जब चाहे उन्हें निकाल देती थी। वह बार-बार पुकारता था कि सरकार कोई विधायक लेकर आए जिससे उसकी सर्विस की सुरक्षा बन सके। अध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी ने एक संशोधन पेश किया है। उन्होंने कहा है कि यह बिल सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाए लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि उन्हें इस बिल में कौन सी खामी नजर आई जिसकी वजह से इसको सिलैक्ट कमेटी को भेजना चाहिए। मैंने इसे क्लोज बाई क्लोज पढ़ा है। यह बिल्कुल पूर्ण बिल है। जो उनका संशोधन है वह यह है कि अगर कोई अनसोशल ऐलीमेंट कालेज में भर्ती हो जाता है तो उसे कोई प्रिंसिपल या मनेजिंग कमेटी निकाल नहीं सकेगी, और वह कालेज में बैठकर गड़बड़ पैदा करेगा। यह संशोधन उनका ठीक है लेकिन यह बताते हुए जिस धारा सात का ये उल्लेख कर रहे थे, उसमें की नहीं लिखा है कि ऐसे असामाजिक तत्व को निकाला नहीं जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, यह तो केवल मात्र उसके ऊपर चैक रखा है और यह चैक बहुत जरूरी है। जैसा मैंने अभी कहा कि आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं कि मैनेजमेंट जिसको चाहे लगाती है और जिसको चाहे निकालती है। ये चैक्स तीन तरह के हैं। पहला चैक यह है कि किसी भी टीचर को बिना जांच किए निकाला नहीं जाएगा। दूसरा चैक यह है कि किसी भी टीचर को बिना सुनवाई का अवसर दिए निकाला नहीं जाएगा। स्पीकर साहब, यह चैक ऐसा है जो प्रिंसिपल आफ नैचुरल जस्टिस में आता है। तीसरा चैक यह है कि डायरेक्ट की एप्रूवल जरूरी है। (विधन) अगर कोई

शिक्षक यह समझें कि उसको निकाला जाना गलत है तो वह उसकी एप्रूवल नहीं देगा। अगर वह समझें कि उसको सही निकाला गया है क्योंकि वह कालेज में गड़बड़ पैदा कर रहा था, कालेज में गैर-सामाजिक वातावरण फैला रहा था तो उसकी एप्रूवल दे सकता है। उसकी एप्रूवल फाईनल होगी।

स्पीकर साहब, सिविल कोर्टस को बार करने का जहां तक संबंध है, मैं नहीं समझती कि भाई बीरेंद्र सिंह जी कैसे इसके बारे में बोल रहे थे। इसका फायदा सबसे ज्यादा मैनेजिंग कमेटी उठाना चाहती थी। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में पहले प्रिलिमिनरी हियरिंग होती है जिसके द्वारा जजिज देखते हैं कि मसला कितना महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें मसला महत्वपूर्ण लगता है तो उसमें हाई कोर्ट के जजिज दखल देते हैं। यदि उन्हें लगता है कि इसमें की कोई ऐसा मसला नहीं है कि इसके अंदर हम गौर से जाना चाहिए या केवल समय नष्ट करने के लिए यह लाया गया है तो वे कच्ची पे पी में उसे खारिज कर सकते हैं जबकि दीवानी मुकदमें तो एडमिट होंगे ही होंगे और वशॉ तक मुकदमें चलते रहेंगे। आपको खुद पता है और हर देहाती और भाहरी को भी पता है कि जब कोई दीवानी मुकदमा कोर्ट में एक बार चला गया तो चार-पांच वर्ष से पहले उसका फैसला नहीं होगा, फिर उसके लिए अपील हाई कोर्ट तक होती है। अगर कहीं सरकार का कोई फैसला गलत हो जाता है तो मैनेजमेंट या टीचर जिसके खिलाफ वह फैसला है और जो भी एग्रीव्ड अपील करता है वह

हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है और वहां से वह न्याय प्राप्त कर सकता है। इसमें दीवानी मुकदमों को खत्म किया जाना इसलिए भी जरूरी था ताकि फैसले में डिले न हो।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जहां जस्टिस डिले हो जाता है वहां जस्टिस डिनाईड समझा जाता है इसलिए न्याय में देरी न हो इस वजह से यह प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, एक मुगालता हमारे साथियों को और है, वह यह है कि जहां डायरेक्टर को अपील का प्रावधान किया गया है वहां उसी डायरेक्टर की एप्रूवल का प्रावधान भी किया गया है। वे यह समझ रहे हैं कि आज जिस डायरेक्टर की एप्रूवल ली जायेगी, अगर फिर उसी डायरेक्टर के सामने कोई अपील होगी तो बहुत बड़ी एनोमली समझी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, वे कुछ गतलफहमी में हैं। वास्तव में सही यह है कि केवल तीन चीजों के लिए डायरेक्टर की एप्रूवल चाहिए और वे तीन चीजें हैं, डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन। अगर मैनेजमेंट ये तीन सजायें देना चाहती है— सजायें तो बहुत हैं लेकिन अगर सारी सजाओं में से ये तीन सजायें देना चाहती है किसी अधिकारी को डिसमिस करना चाहती है, रिमूव करना चाहती है या उसके रैंक में रिडक्शन करना चाहती है तो डायरेक्टर की एप्रूवल जरूरी है लेकिन अगर तीनों के अलावा कोई और सजा देना चाहती है तो एप्रूवल जरूरी नहीं है। फिर टीचर को अख्तियार है कि वह डायरेक्टर के पास अपील कर सकता है यानी ये दो चीजें अलग अलग हैं। जिस में एप्रूवल

होगी उसमें अपील का प्रावधान नहीं है लेकिन इन तीनों के अलावा कोई और सजा देते हैं तो डायरेक्टर के पास अपील कर सकता है यानी ये दो चीजें अलग अलग हैं। जिसमें एप्रूवल होगी उसमें अपील का प्रावधान नहीं है लेकिन इन तीनों के अलावा कोई और सजा देते हैं तो डायरेक्टर के सामने अपील कर सकते हैं। इस तरह की कोई एनोमली इस बिल में नहीं है और मैं चौधरी रिजक राम जी से कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी कमी इस बिल में नहीं है। अगर इस बिल को और लटकाया गया तो जो 32 वर्षों से समस्या लटकी चली आ रही थी वह और भी लटक जायेगी। हम चाहते थे कि दो वर्ष इस सरकार को बने हुए हो गये हैं इसलिए यह बिल पहले ही आना चाहिए था। मैं तो कहूँगी कि यह देर से आ रहा है पहले आना चाहिए था। उनको पहले ही यह सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। अब यह बिल आज आया है तो इसको पास करने में किसी प्रकार की डिले नहीं होनी चाहिए। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल सरकार लाई है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूँ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और रह गई जिसको मैं कहना चाहूँगी। एक तरफ तो हम सर्विस सिक्वोजिटी टीचर्स को दे रहे हैं, दूसरी तरफ मैं आपके द्वारदा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इन्होंने जो सर्वे कमेटी की रिपोर्ट मंगवाई थी, जब आप शिक्षा मंत्री थे, उस टाइम पर वह कमेटी नियुक्त हुई थी। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने एप्रूव कर दिया है।

सर्वे कमेटी की रिपोर्टों में इन की बिनाह पर एक लैटर डी०पी०आई० आफिस से सारे कालेजिज को गया है। उसमें यह कहा गया है कि वर्ष 1978-79 के लिए उनको ए०डी०ए० की इन्स्टालमेंट उसी तरह से दे दें जैसे गवर्नमेंट कालेजिज को दी जाती है। उसके मुताबिक कालेजिज ने दे दी लेकिन अध्यक्ष महोदय, पता नहीं यह कैसे गलती हुई कि उसके बाद एक लैटर कालेजिज को एजुके ान मिनिस्टरी की तरफ से गया है जिसमें यह लिखा है—

“Full ADA should be paid by private colleges w.e.f. 1-4-79. The decision whether arrears are to be paid should be left to the management of these institutions. Arrears will not form a part of expenditure for calculating deficit to determine the maintenance grant.”

श्री अध्यक्ष: इसका यहां पर क्या संबंध है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: इसका संबंध यह है कि एक तरफ तो हम उनको सर्विस सिक्योरिटी दे रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने इसमें यह लिख दिया है। यह जो लैटर 1.4.79 से ए०डी०ए० देने के लिए गया था उसके मुताबिक तो 1978-79 का पैसा दिया जा चुका है लेकिन आज ये कह रहे हैं कि हम इसको खर्च में भामिल नहीं करेंगे। इससे तो सारी की सारी मैनेजमेंट्स इस खर्च को वापिस मांगेगी। दो-दो हजार रुपये टीचर्स को दिय जा चुके हैं और अब उनसे वापिस मांगे जायेंगे क्योंकि इस पैसे को खर्च में भामिल करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। यह इतनी बड़ी एनोमली है कि वे लोग परे ान होंगे। यह

एनोमली आज सामने आई है। उस समय सामने नहीं आई वरना मैं तब भी इस बात को रख सकती थी। इस बात को मैं एजुके इन मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहती थी कि अगर यह कर दिया गया तो बहुत बड़ा नुकसान टीचर्ज को होगा क्योंकि जिन को पैसा मिल चुका है उनसे मैनेजमेंट वापिस मांगेगी। सरकार को बलिक इतना करना चाहिए कि जहां 1.4.79 लिखा है वहां पर 1.4.78 कर दिया जाये। शिक्षा मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हैं। आप उनसे मिल कर 1.4.78 करवा दें तो सारे का सारा मसला हल हो जायेगा और सारे के सारे टीचर्ज आपको बधाई देंगे। इतना कह कर मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत भुक्तिया कि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया है। एक दो बातें ही मैं तोड़ की कहना चाहता हूं। स्पीकर साहब, विधान सभा का सै इन एक महीने तक चला है और रोजाना ही हमारे आनरेबल मिनिस्टर श्री हीरा नंद आर्य ने माना है कि आजकल पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है। इसलिए मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं कि यह कोई मामूली बिल नहीं है, यह बड़ा इम्पौरटेंट बिल है। यह बिल ने इन को बनाने वालों से संबंध करता है। ये कौम के निर्माता है इसलिए इस बिल को सोच विचार कर यहां से पास किया जाना चाहिए। मैं तो इस बारे में

यह भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्कूल हैं सब को ने एनेलाइज किया जाना चाहिए इसके सिवाए कोई परमानेंट इलाज नहीं है यह जो इलाज किया जा रहा है यह भी टैम्पोरेरी हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारि है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेजा जायें। उस कमेटी में गौर होने के बाद यहां पर लाया जाये। सिलैक्ट कमेटी में जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के भी मैम्बरज भागमिल होने चाहिए। यह सारे हरियाणा का सवाल है। इस मौजूदा बिल में अदालत का गला घोटा है और इसे अदालतों से दूर रखा गया है जोकि गलत बात है। सिर्फ गुड फेथ वर्ड कहने से किसी का भला नहीं हो सकता। किसी को नौकरी से हटा देने पर भी वह अदालत में न जा सके तो यह सारा ही अनडैमोक्रेटिक है। एमरजेंसी के टाईम में भी बहुत जुल्म हुए क्योंकि उस टाईम भी लोग अदालतों में नहीं जा सकते थे। इसलिए हमें तकलीफें सहन करनी पड़ी। हमे हाईकोर्ट में भी नहीं जान दिया गया और हम को जेलों में सड़ना पड़ा। स्पीकर साहब, आप बड़े तजुर्बेकार हैं और मिलिटरी में रहे हैं इसलिए इसको पास न करवाया जाये और सिलैक्ट कमेटी में भेज दिया जाये। जिस तरह से एमरजेंसी में जुल्म हुए हैं, वे दोबारा न करवायें जाये। अदालत में जाने का अधिकार होना चाहिए। हम सभी ने एमरजेंसी के दिनों में तकलीफें भुगती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल सिलैक्ट कमेटी में भेजा जाये। चौधरी रिजक राम जी तो बदकिस्मती से यहां पर मैम्बर बन बैठे हैं, ये तो बहुत ही पुराने आदमी हैं, इनको वजीर होना चाहिए था

ताकि हरियाणा में अच्छी तरह से राज को चलाते। इन लफ्जों के साथ मैं फिर दोबारा अर्ज करता हूँ कि इस बिल को पास ने किया जाये और इसे सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाये।

श्रीमती भांति देवी(कलियाना): स्पीकर साहब, प्राइवेट कालेजिज के टीचर्ज का सेवा सुरक्षा बिल आज हमारे समक्ष आया है, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देती हूँ और स्पीकर साहब, आपको भी बधाई देती हूँ क्योंकि आपने इसकी पहल की थी और इस ओर कदम बढ़ाया था। उस बएते हुए कदम का अब आर्य जी ने स्वागत किया है। इन्होंने बहुत ही मेहरबानी की है और इस बिल को तैयार करवाने में बड़ी सूझ-बूझ से काम लिया है। तीस साल के कांग्रेस भासन में आपको पता होगा कि इन कालेजिज की क्या हालत होती थी। मैं आपके सामने चंद कालेजिज के नाम बताना चाहती हूँ। उनमें डी0ए0वी0 कालेज, हसनगढ, अहीर कालेज, रेवाड़ी, द्रोणाचार्य कालेज , गुड़गांवा और जाट कालेज, रोहतक है। इन सभी कालेजों की जो हालत बहुत ही बुरी है। उन्होंने वहां पर व्यवसायिक केंद्र बना रखें है। डी0ए0वी0 कालेज हसनगढ में हमारे प्राध्यापकों की काफी बुरी हालत रही है। उनको किसी भी टाईम पर कालेज से भांट-आउट कर देते है। कई प्राइवेट कालेजों में इतनी अधिक खराब हालत है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। वेतन के बारे में आप देख लीजिए। उनसे हस्ताक्षर तो 1500 रू0 पर करवाते है और उनको देते है केवल पांच सौ या सात सौ। सरकार जो उनको

ग्रांट देती है उसमें से प्राध्यापको को पूरी राशि नहीं दी जाती है बल्कि उस ग्रांट को दूसरे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। इस कलंक को हमारी जनता सरकार ने मिटाया है इसके लिए सरकार को जितनी बधाई दी जाये उतनी ही थोड़ी है। हसनगढ़ कालेज की बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। वहां पर जब मैनेजमेंट की इन्कवायरी हो गई तो वहां की मैनेजमेंट बोखला गई और यह डिक्लेअर कर दिया कि यहां हम कोई कालेज नहीं चला रहे हैं। उसका अंजाम आपके सामने है के पहले हाई कोर्ट से हारे और अब सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हैं क्योंकि वे डिक्लेयर कर चुके हैं कि कोई कालेज फंक्शन नहीं कर रहा है। 15-20 साल की सर्विस वाले प्राध्यापक रातों पर पान रहते थे, बेचैनी की नींद सोते थे कि पता नहीं किस टाइम पर क्या हालत हो जाये? एक प्राध्यापक को यह पता नहीं होता था कि आज अगर उसके मुंह से कोई छोटी-मोटी बात मैनेजमेंट के खिलाफ निकल गयीतो वह सवेरे नौकरी में होगा भी या नहीं होगा। इससे ज्यादा बड़ा कलंक हमारे इन कांग्रेसियों के लिए और क्या हो सकता है? इस सरकार ने बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया है और मैं इसकी पुरजोर तारीफ करती हूँ। चौधरी रिजक राम जी ने जिनको कालेजों के बारे में कोई एक्सपोरिऐंस नहीं है, एक संतोष दिया और अपनी मनमर्जी से ही बगैर हमारी जानकारी के सात सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त कर दी। अपने अनुमान से ही इन्होंने यह कमेटी नियुक्त कर दी है। इसमें चार आदमी ऐसे हैं जो इसका विरोध करते और भायद तीन आदमी ऐसे हैं जो इसका समर्थन

करते। बड़ी चतुराई से अपनी बुद्धिमता का इन्होंने उसमें परिचय दिया है कि तीन हक में जायेगे और चार उसके उलट जायेंगे तो आर्य जी इनकी बात का मान लेंगे। मेरा कहना यह है कि इनको हरेक मैम्बर को पहले परखना चाहिए था। एक तो ये स्वयं है एक इसमें प्रोफैसर को रख लिया और एक आध भायद हमारे जैसे मैम्बर को इसलिये रख लिया कि हो सकता है हमें अपने प्रभाव में ले लें। मैं उनकी इस अमेंडमेंट का समर्थन नहीं करती क्योंकि अगर किसी प्राध्यापक के खिलाफ कोई शिकायत है, वह बुरा आदमी है, या कोई एंटी सोशल एलीमेंट है, अगर उसके खिलाफ चार्जिज प्रूव हो जायें तो उसे वैधानिक ढंग से निकाला जा सकता है। उसके लिए कोई दरवाजा आर्य जी ने बंद नहीं किया। इन भावों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र भार्मा (थानेसर): स्पीकर साहब, इस बिल को लाने से सिलैक्टिड क्लास आफ दि सोसाइटी यानी इंस्टैलैक्चुअल सैव इन आफ दि सोसाइटी का कल्याण किया जा रहा है, मैं इसके लिये अपनी तरफ से सरकार को बधाई देता हूँ। मगर कुछ टर्म्ज इस बिल में ऐसी है जिनका वेग तौर पर इस्तेमाल किया गया है। स्पीकर साहब, भांति राठी जी तो खुद टीचर रही है। मेरा किसी कालेज की मैनेजमेंट से या किसी कालेज से किसी किस्म का वास्ता नहीं है। मैं प्रोफैसर लोगों से ज्यादा रहता हूँ क्योंकि मैं खुद पी0एच0डी0 कर रहा हूँ। इस लिहाज से प्रोफैसर

लोगों के बीच मेरा रहना मुनासिब भी है। मेरी इच्छा यह थी कि मैं भी एक प्रोफ़ैसर लोगों के बीच मेरा रहना मुनासिब भी है। मेरी इच्छा यह थी कि मैं भी एक प्रोफ़ैसर बनूँ क्योंकि मैंने देखा कि यू०जी०सी० ग्रेड मिलने के बाद यह सारे हिन्दुस्तान भर में सबसे ज्यादा पे लेते हैं और काम का जहाँ तक ताल्लुक है, काम सबसे कम करते हैं। (व्यवधान व भाोर)

श्रीमती भांति देवी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। यह प्राइवेट कालेज के टीचर्ज की सेवा सुरक्षा का बिल है न कि उनके वेतन का। उनको जो नये ग्रेड दिये गये हैं वे वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिये गये हैं और लागू किये गये हैं.....

श्री देवेन्द्र भार्मा: मेरी बात को जरा ध्यान से रुन लैं मैं आगे उसी बात पर आउंगा। इसी यू०जी०सी की रिपोर्ट में यह लिखा है कि यह पे—स्केल देने के बाद उनको इतना टाईम कालेज में जरूर रहना पडेगा। उसको कोई ट्यू इन नहीं करनी चाहये और उसके अलावा जो एग्जामिने इन का काम होता है , वह भी करना पडेगा । एग्जामिने इन का दो तरह का काम होता है एक तो सुपरवीजन का और दूसरा कापियां देखने का। मैं इन प्रोफ़ैसर्ज को आई०ए०एस० अफसरों से भी इन्टैलीजन्ट मानता हूँ क्योंकि इसमें वही लोग आ पाते हैं जो फर्स्ट क्लास ग्रैजुएट्स या पोस्ट ग्रैजुएट्स होते हैं जबकि इनके मुकाबले में कोई भी थर्ड क्लास ग्रैजुएट्स एग्जाम में बैठ कर आई०ए०एस० बन सकता है। अब तो

इस बिल के जरिये इतनी ज्यादा प्रोटैक्शन दे दी गयी है। कि जो प्रौफेसर काम नहीं करते उनके खिलाफ भी मैनेजमेंट अगर जायज तरीके से एक एन लेना चाहे तो वही नहीं ले सकती है। स्पीकर साहब, इतना लैन्थी प्रोसेस बना दिया गया है कि किसी के खिलाफ यदि कोई एक एन लेना हो तो चार सौ किस्म की कार्यवाही करनी पड़ेगी। स्पीकर साहब, 1975 से लेकर 1977 तक एमरजेंसी के दौरान जो प्रौफेसर अपनी सर्विस से हाथ धो कर बैठे रहे, उनको कोई स्टैच्युरी प्रोटैक्शन नहीं। सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने हालाकिं स्टेट गवर्नमेंटस को यह डायरेक्टिव एन दी कि जितने टाइम तक ये प्रोफेसर्स सर्विस से बाहर रहे, उस टाइम का उनको पैसा दे दो लेकिन अभी तक भी उनको कोई पैसा नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: कृपया बिल के बारे में ही रैलेवैन्ट बात कहें।

श्री देवेन्द्र भार्मा: चौधरी रिजक राम जी ने जो अमेंडमेंट इस बिल के बारे में दिया है उसके बारे में मैं बर्ज यसको थोडा सा आब्जेक्शन है। इसलिये या तो वे खुद उसमें चेंज कर सकते हैं या फिर आपको अखितयार है, आप उमें चेंज कर सकते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि इस बिल को जल्दी से पास किया जाये क्योंकि यह एक बडा टच्ची सा मामला है और सारी स्टेट की पढाई को अफैक्ट करता है। इस बिल से एक बहुत बडे सैक्शन का भला होने वाला है, इसे तो पहले ही पास कर देना चाहिये

था। अब क्योंकि यह बिल आया है, चाहे देर में ही आया है, इसे पास कर देना चाहिये। इसमें जो वेग सी टर्ज है उसके बारे में मैनेजमेंट भी औब्जैक्ट करेगी और हो सकता है प्रोफ़ैसर भी इस बारे में औब्जैक्ट करे और इससे किसी भी प्राइवेट कालेज में कन्जीनियल एटमोस्फीयर नहीं रहेगा। इसलिये मैं चौधरी रिजक राम जी के पास सं गोधान के साथ हूँ। कि इसके लिये एक कमेटी भी बना दी जाये। धन्यवाद।

वित्त मंत्री (श्री मूलचन्द जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस रीडिंग पर क्लोजर मो इन मूव करता हूँ कि डिबेट अब क्लोज की जाये।

श्री अध्यक्ष: मेरा विचार है कि अभी एक-दो मँबर और बोल लें।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़): स्पीकर साहब, मैं इस बिल को लाने के लिये बजुके इन मिनिस्टर साहब का और सरकार का भुक्तिया अदा करता हूँ कि वे यह बिल लाये है। लेकिन इस बिल के साथ ही इसमे यह भी जोड दिया जाये कि जो अध्यापक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते है या पढ़ाती है, वे अक्सर पीरियड में नही पढ़ाते। कालेजों में भी यही होता है कि अध्यापिकायें अक्सर स्वेटर बुनती रहती है पढ़ाती नही है। अब यह बिल आने से उनकी नौकरी को और ज्यादा हिफाजत हो गयी है इसलिये वे अब और ज्यादा काम नहीं करेगी। इसलिये मैं यह

चाहता हूँ कि इस विधेय में यह भी जोड़ दिया जाये कि जो अध्यापिकायें बच्चों को न पढायें उनको हटा दिया जाये।

श्रीमती भान्ति देवी: स्पीकर साहब, बात चल रही है वि विद्यालयों की, ओर ये महानुरुभाव स्वेटर बुनने की बात कह रहे ह। यह उचित बात नहीं लगती।

चौधरी लाल सिंह: मैं सब के बच्चों की रक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि एक कालेज नारायणगढ़ में भी खोल दिया जाये।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं बर साहिबा भी गलत बोल गयी है। उन्होंने यह कहा कि वि विद्यालय की बात चल रही है, यहां पर महाविद्यालय की बात चल रही है वि विद्यालय की नहीं चल रही है।

श्री अध्यक्ष: चौधरी रिजक राम जी, क्या आप अपनी अमेंडमेंट वापिस लेना चाहते हो?

चौधरी रिजक राम: पहले मंत्री महोदय अपने विचार बता दें, उसके बाद मैं एक मिनट ले लूंगा।

शिक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य): अध्यक्ष महोदय, जो बिल मैंने हाउस में पे र किया है उसके बारे में जो चर्चा हुई है, उसमें चौधरी रिजक राम जी ने यही कहा है कि यह बिल बहुत जल्दबाजी में पे र किया गया है। इसलिये चौधरी साहब ने अपनी

अमैंडमेंट पे 1 की है। स्पीकर साहब, आपको याद होगा, जनता पार्टी का भासन आते ही जब आप शिक्षा मंत्री थे तो उस वक्त एक सर्वे कमेटी मुकर्रर की गयी थीं क्योकि आपको याद होगा सब जगह प्राइवेट कालेजिज के प्रोफसर्ज से लगातार मांग आ रही थी कि उनकी सर्विस सिक्योरिटी नहीं है, वह उन्हें प्रदान की जाये। लोगों ने प्राइवेट कालेजिज को एक तरह से दुकानें बना रखा था। इन दुकानों में एम्पलाईज को बड़ी बेरहमी के साथ और गलत तरीके से निकाला जाता था। अध्यक्ष महोदय, उस सर्वे कमेटी में सरकार की तरफ से डी0पी0आई0 और दूसरी तरफ प्राइवेट कालेजिज की मैनेजमेंटस के मैबर्ज तथा एम्पलाईज के रिप्रेजेन्टैटिव्ज थे। बड़े विस्तार से उस मामले पर विचार किया गया। उस कमेटी के विचार करने के बाद यह मामला कैबिनेट के सामने आया। कैबिनेट में आने के बाद फिर एक सब-कमेटी ओर बनाई गई और इसको पूरी तरह से एग्जामिन किया गया। क्योकि शिक्षा का मामला ऐसा मामला है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है इसलिये कैबिनेट की एक सब-कमेटी बनाई गई और बड़ी गहराई से शिक्षा की इस गम्भर समस्या को देखा गया। स्पीकर साहब, सिक्योरिटी आफ सर्विस का एक्ट बहुत पहले आ जाना चाहिये था लेकिन इसमें काफी देर हो गई है। मैं ज्यादा न कहते हूये इतना ही कहना चाहता हूं कि चौधरी रिजक राम और देवेन्द्र भार्मा ने कुछ एतराज किये है लेकिन इन्होने किसी भी सैव न या किसी भी क्लाज के बारे मे कोई ठोस सुझाव नहीं दिया है कि

क्यो अमैंडमेंट होनी चाहिये। अगर ये कोई ठोस सुझाव दे तो उसके बारे में सोचा जा सकता है।

चौधरी संत कवर : आन ए प्वांयट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मैं वजीर साहब से क्लेरीफिके इन चाहता हूं कि जो प्राइवेट आयुर्वेदिक कालेज है, वे भी इसमें शामिल हैं या नहीं?

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, यहा पर मिसयूज आफ पावर की बात कही गई है। सिक्योरिटी आफ सर्विस एक्ट स्कूलज के सम्बन्ध में भी है। मैं नहीं समझता कि सरकार ने कभी मिसयूज आफ पावर की हो। अगर ये स्कूल के सम्बन्ध में मिसयूज आफ पावर का एक भी इंस्टांस दे देते जिसमें एम्पलाइज के साथ कोई ज्यादती की गई हो तो मैं मानता और वास्तव में मैं सोचता कि विचार करने की कोई बात है। स्पीकर साहब, जैसा कि मेने पहले कहा कि इस तरह का बिल पहले ही आ जाना चाहिये था और अब मैं प्रार्थना करूंगा कि चौधरी रिजक राम अपनी अमैंडमेंट विदद्दा करें क्योंकि यह बिल बडे सोच विचार के बाद लाया गया है।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह बिल सरकुलेट होने के बाद मंत्री महोदय से मेन विचार विम र्फ किया था औरउन्होने अपनी राय जाहिर की थी कि उनको सिलेक्ट कमेटी में भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। उसी विचार को सामने रखकर यह सं गोधन पे र किया गया था। मैं दो भाब्दों में एक

बात कहना चाहता हूं कि ऐम्पलाइज आर्बिट्रे इन कोड के तहत ऐम्पलाइज वाइस चांसलर को रैफ्रेन्स के लिये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि that matter should be referred to arbitration और उसमें एक टीचर्ज का नुमांइदा, एक मैनेजमेंट का और वाइस चांसलर ये तीनों बैठकर जो फैसला करे वह माना जाता है इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। बहिन भांति राठी ने कहा कि इनको कोई कालेज चलाने का ऐक्सपीरिएंस नहीं है लेकिन मैं फख के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी संस्था का इंतजाम हमारे हाथ में है जो हरियाणा और पंजाब में ही नहीं भारत में उत्तम स्थान रखती है। पहली तारीख नहीं होने पाती कि उसके अध्यापको को चैक के जरिये तनखाह दी जाती है। गवर्नमेंट ने जो ग्रेडज मुकर्रर किये हैं वे वहां पर भी मुकर्रर किये हुये उस सारी संस्था में आठ नौ हजार स्टूडेंटस हैं रिजल्ट का यह हाल है कि पहला, दूसरी तीसरा चौथा और पांचवा स्थान मैरिट लिस्ट में उस संसिी के विद्यार्थियों का होता है शिक्षा का माहौल ऐसी होना चाहिये कि वहां पर गुटबन्दी न हो और आपस में नाराजगी का माहौल पैदा नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा माहौल होगा तो शिक्षा चल नहीं सकती। स्पीकर साहब, मैं एक किताब पढ रहा था उसमें बडे सियाने आदमियों ने बातें लिखी हैं। उसमें लिखा है कि अगर महिला कोई गलत बात भी कहती है तो भी उनसे जिद नही करनी चाहिये। बहिन सुशमा जी ने और भांति राठी ने बहुत सी बातें की है। उनकी बातें मानना ही ठीक है क्योकि उन्होंने तो मानना ही नहीं है। इसलिये मैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुये और आ

करते हुये कि इस बिल को लागू करने में इस बात का ध्यान अव य रखा जायेगा कि शिक्षा जो विद्यार्थियों की जिन्दगी का सवाल है उसमें कोई अडचन न होने पाये । मैं टीचर्ज का बडा आदर करता हूं लेकिन कुछ ऐसी बातें होने लगी है जो कभी सोची भी न थी। लडको के इम्तहान होने लगते है और टीचर्ज हड़ताल पर बैठ जाते है। मैने देखा है कि जनवरी और फरवरी के महीने बच्चों के पढाई के महीने होते है और उस वक्त वे हड़ताल पर चले जाते है। आज के टीचर्ज के दिल में विद्यार्थी काहित नहीं है। वे शिक्षक कहलाने के हकदार नहीं है। बच्चों के कैरियर का सवाल है, बच्चों के भविश्य का सवाल है और वे स्ट्राइक पर चले जायें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। आप उनके हित की बात सोच रहे है लेकिन जो कुछ मैने कहा है सरकार उस पर गोर कर लें क्योंकि यह किसी की जायदाद नहीं है। सरकार का ध्येय है कि स्कूल ओर कालेजों का वातावरण अच्छा रहे, शिक्षा का स्तर उंचा रहे। मुख्य मंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री के सामने भी वही कठिनाइयों है जो हमारे सामने है ओर मैं समझता हूं कि वे उन पर विचार करेगे।स्पीकर साहब जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने फरमाया है उसको ध्यान में रख कर मैं चाहता हूं कि मैनें जो संशोधन पे किया है उसको वापिस ले लूं। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं और अपनी जगह लेता हूं।

Mr. Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment?

(Voices: Yes)

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Me. Speaker: Question is-

That the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

आवाजें: इक्कठी ही पुट कर दें ।

क्लाजिज 2 से 7

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि क्लाजिज 2 से 7 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 8

चौधरी वीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, क्लाज 8 के बारे में मैं यह कहूंगा कि एक तो जुडिियल ओर क्वासी जुडिियल प्रोसीडिगज होती है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिगज होती है। अगर इसमें सिविल कोर्टस को डिबार किया जाता है तो जो भी प्रोसीडिगज होगी चाहे उसे डी0पी0आई0 एज प्रजाइडिंग अफसर करे, वे सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव

प्रोसीडिंग्स होगी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जो यह ख्याल है कि वे अध्यापको की सर्विस की सिक्योरिटी के लिये यह बिल ला रहे हैं तो मैं उनके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि इस बिल के द्वारा उनका हित नहीं बल्कि अहित हो रहा है क्योंकि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हों तो यह उनका अहित ही होगा। इसमें सरकार का फैसला आखिरी रखा गया है। इससे सरकार मैनेजमेंट के दबाव में आकर बहुत से ऐसे काम करेगी जिनसे अध्यापको का अहित होगा। इसलिये मैं दख्तास्त करूंगा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुये मंत्री महोदय इस कालज को वापिस ले लें। अगर वे इसको वापिस नहीं लेना चाहते तो हमस दन से वाक आउट कर जायेगें। ऐसा करने से मौलिक अधिकारों का गला घोटने वाली बात है। यह सरकार दावे करती थी कि हम प्रजातन्त्र को बहाल करेगें और इनके चुनाव घोशणापत्र में भी यह बात थी कि हम दलित वर्ग को और छोटे आदमी को अदालतों तक जाने का अवसर देगें लेकिन इस बिल के द्वारा ये समाज के सब से इन्टेलीजेंट वर्कर को अदालतों में जाने से रोक रहे हैं। इसे बडा अप्रजातन्त्रिक काम कोई नहीं हो सकता। ये ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती।।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि

कि कलाज 8 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वाक आउट

आवाजें: स्पीकर साहब, इसके विरोध में हम एज ए प्रोटेस्ट वाक आउट करते हैं।

(इस समय सर्वश्री बीरेन्द्र सिंह, जगजीत सिंह पोहलू मांगे राम गुप्ता और इन्द्रजीत सिंह वाक आउट कर गये)

दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्वोरिटी आफ ससर्विस) बिल, 1979 (पुनरारम्भ)

क्लाजिज 9 से 16

श्री अध्यक्ष: प्र न है —

कि क्लोजिज 9 से 16 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न है —

कि क्लोज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र न है -

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्र न है -

कि टाइटल बिल का टाइटल बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिक्षा मंत्री (श्री हीरानन्दआर्य): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

दि हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि-

दि हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि-

दि हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक
पास किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित
किया जाता है ।

13.45 बजे

(The Sabha then *adjourned Sine-die.)